डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2024-2026
लाइसेंस क्र. Tech/23-04/08/2024-2026
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 24.02.2025 से 02.03.2025 ▶ वर्ष-42 ▶ अंक-09 ▶ मूल्य ₹ 10.00

MPIDC
MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश
अनंत संभावनाएं

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
के दूरदर्शी नेतृत्व में

देश का हृदय प्रदेश लिख रहा
विकास की नई गाथा

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
उद्घाटन

प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी
द्वारा
गरिमामयी उपस्थिति

मंगुभाई पटेल
राज्यपाल, मध्यप्रदेश

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

CII Confederation of Indian Industry

24 फरवरी, 2025 | प्रात: 10:00
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल

EY Shape the future with confidence

सीधा प्रसारण Webcast.gov.in/mp/cmevents DD News @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP

www.investmp.in

D-11193/R-50621/2025

MPIDC MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD. | CII Confederation of Indian Industry | EY Shape the future with confidence

अनंत संभावनाओं की भूमि मध्यप्रदेश में आपका स्वागत है

औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दृढ़ प्रतिबद्धता से मध्यप्रदेश में निवेश का मजबूत ईको सिस्टम विकसित हुआ है। अपनी निवेशक अनुकूल नीतियों एवं 'स्टार्ट योर बिज़नेस इन 30 डेज़', एकल खिड़की व्यवस्था, ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस में अग्रणी एवं अपार संसाधनों के साथ प्रदेश निवेश के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश

अनंत संभावनाएं

उद्योग एवं रोज़गार वर्ष - 2025

कार्यक्रम

24 फरवरी 2025

प्रातः 7:30	पंजीयन
	सेक्टर आधारित सत्र
प्रातः 11:45–सायं 6:30	टेक इन्वेस्ट – समिट हॉल 1
प्रातः 11:45–दोपहर 2:00	नवीनीकृत मध्यप्रदेश – समिट हॉल 2
दोपहर 3:15 - सायं 7:00	फीडर सोलराइजेशन समिट : 2000 मेगावॉट कुसुम सी की प्रीबिड – समिट हॉल 2
	पार्टनर कन्ट्री सेशन
प्रातः 11:45 –दोपहर 12:45	ग्लोबल साउथ पर सेशन – कॉन्फ्रेंस हॉल
दोपहर 12:45–1:45	जर्मनी और मध्यप्रदेश के लिए निवेश रणनीतियों पर सत्र – कन्ट्री सेशन हॉल
दोपहर 3:30–सायं 4:30	जापान और मध्यप्रदेश के बीच आर्थिक सहयोग पर सत्र - कन्ट्री सेशन हॉल
	थीमेटिक सेशन
प्रातः 11:45–दोपहर 12:45	मॉलिक्यूल टू मशीन (फार्मा एवं मेडिकल डिवाइसेस)- सेशन हॉल 1
दोपहर 1:15–2:15	इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल (स्किल डेवलपमेंट) - सेशन हॉल 1
सायं 4:30–5:30	सड़क निर्माण के बुनियादी ढांचे में गति लाना : निवेश, नवाचार और संभावनाएं - सेशन हॉल 3
	सीआईआई मीटिंग
दोपहर 2:00-3:00	महिला उद्यमियों एवं स्टार्ट-अप्स के लिए नेटवर्किंग के अवसरों पर सीआईआई आईडब्ल्यूएन सत्र - कॉन्फ्रेंस हॉल
दोपहर 3:00–सायं 4:00	सीआईआई राष्ट्रीय वस्त्र एवं परिधान समिति- कॉन्फ्रेंस हॉल
सायं 4:00–5:00	सीआईआई राष्ट्रीय एमएसएमई काउंसिल मीटिंग - कॉन्फ्रेंस हॉल
सायं 5:00-7:00	द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग- कॉन्फ्रेंस हॉल
दोपहर 3:30–सायं 4:00	एमओयू सेशन – सेशन हॉल 3

25 फरवरी 2025

	सेक्टर आधारित सत्र
प्रातः 9:30–11:15	मध्यप्रदेश प्रवासी समिट- समिट हॉल 2
प्रातः 10:30–दोपहर 12:30	पर्यटन समिट- समिट हॉल 1
प्रातः 11:30–दोपहर 1:30	माइनिंग समिट- समिट हॉल 2
दोपहर 2:00–सायं 4:00	एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप समिट – मुख्य हॉल
दोपहर 2:00–सायं 4:00	शहरी विकास समिट- समिट हॉल 1
	प्री-बिड सेशन
प्रातः 10:00–11:30	मुरैना सोलर- बीईएसएस प्रोजेक्ट– सेशन हॉल 1
प्रातः 11:30–दोपहर 12:00	मुरैना यूपी-एमपी कॉम्प्लिमेन्टैरिटी प्रोजेक्ट- सेशन हॉल 1
दोपहर 12:00–2:00	रूफटॉप सोलर (RESCO)- सेशन हॉल 1
	पार्टनर कन्ट्री सेशन
प्रातः 10:30–11:30	कनाडा राउन्ड टेबल- कॉन्फ्रेंस हॉल
दोपहर 12:00–1:00	बहुराष्ट्रीय निवेश सत्र- कन्ट्री सेशन हॉल
दोपहर 2:30–3:30	पोलैंड कन्ट्री सेशन- कन्ट्री सेशन हॉल
	थीमेटिक सेशन
प्रातः 10:30–11:30	नए युग का आरंभ (वस्त्र एवं परिधान)- सेशन हॉल 2
प्रातः 11:00–दोपहर 12:30	फ्यूचर फ्रंटियर्स- एमपी स्टार्टअप पिचिंग सेशन- सेशन हॉल 3
दोपहर 12:00–1:00	सीड टू शेल्फ (खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवानी)- सेशन हॉल 2
दोपहर 12:30–1:30	थीमेटिक सेशन (को-ऑपरेटिव)- सेशन हॉल 3
दोपहर 2:30–3:30	ग्रीन हाइड्रोजन- सेशन हॉल 1
दोपहर 2:00–3:00	लॉजिस्टिक्स: दुनिया से जुड़ता मध्यप्रदेश- सेशन हॉल 2
	इन्वेस्ट मध्यप्रदेश समापन सत्र
सायं 4:30–6:00	ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट - मुख्य हॉल

फोकस सेक्टर

- कृषि, खाद्य और डेयरी प्रसंस्करण
- ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स
- टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स
- फार्मा, मेडिकल डिवाइस और हेल्थ केयर
- आईटी/आईटीईएस/ ईएसडीएम
- नवीकरणीय ऊर्जा
- लॉजिस्टिक्स एवं भंडारण
- प्राकृतिक गैस एवं पेट्रो रसायन
- एयरोस्पेस एवं डिफेंस
- पर्यटन
- माइनिंग
- कौशल निर्माण
- शहरी विकास

अधिक जानकारी के लिये
invest.mp.gov.in

मुख्य आकर्षण

- एमपी मोबिलिटी एक्सपो
- सेंट्रल इंडिया फेब्रिक एंड फैशन एक्सपो
- ओडीओपी विलेज
- कन्ट्री सेशन
- एमपी पवेलियन
- एग्जीबिशन एवं एक्सपो
- एमपी बिजनेस एग्जीक्यूटिव मीट (बीटूबी मीटिंग)
- मध्यप्रदेश सरकार एवं बिजनेस मीट (बीटूजी मीटिंग)

D-11193/R-50621/2025

डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2024-2026
लाइसेंस क्र. Tech/23-04/08/2024-2026
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 24.02.2025 से 02.03.2025 ▶ वर्ष-42 ▶ अंक-09 ▶ मूल्य ₹ 10.00

मुख्यमंत्री ने 89 हजार 710 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए सिंगल क्लिक से जारी किए 224 करोड़ रुपये

विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलने से प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं होंगी सशक्त

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रतिभाशाली मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए

- राज्य सरकार के सभी संसाधनों पर समाज के कमजोर से कमजोर तबके का है अधिकार।
- अपने परिश्रम से उपलब्धियां अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने का आनंद वर्णनातीत।
- प्रत्येक विद्यार्थी 25-25 हजार की राशि से अपनी पसंद से ले सकेंगे लैपटॉप।

भोपाल, परिवार परंपरा में मां द्वारा अपने बच्चों को पुष्पित, पोषित करने में प्राप्त आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता इसी प्रकार प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वह वर्णनातीत है, यह जीवन भर याद रहने वाली अनुभूति है। जैसे परिवार में सदस्यों का सभी संसाधनों पर अधिकार होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार के सभी संसाधनों पर समाज के कमजोर से कमजोर तबके का अधिकार है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासन अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 89 हजार 710 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप लेने के लिए 224 करोड़ की राशि अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने से उनकी प्रतिभा निखेरेगी, जिससे प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं अधिक सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें उपलब्ध कराई जा रही 25-25 हजार रुपये राशि का उपयोग लैपटॉप क्रय में ही किया जाए। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा वर्ष 2023-24 में कक्षा 12 में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके बैंक खातों में 25-25 हजार रुपये की राशि लैपटॉप खरीदने के लिए अंतरित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में विद्यमान गुरुकुल परंपरा जातियों और वर्ग भेद से मुक्त थी। सभी को समान रूप से सभी व्यवस्थाओं के लिए अधिकार देकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता था। इसी की निरंतरता में विद्यार्थियों को तकनीक के उपयोग से ज्ञानार्जन और कौशल विकास में मदद मिलेगी।

देश भक्ति के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व का श्रेष्ठतम लोकतंत्र भारत है। यह लोकतांत्रिक गणतंत्र लंबे संघर्ष के बाद स्थापित हुआ है। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, शहीद-ए-आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन यह बताता है कि मेधावी होने के साथ देशभक्त होना जरूरी है। नेताजी ने अपनी मेधा के बल पर भारतीय प्रतिभा की प्रावीणयता को संपूर्ण विश्व में स्थापित किया और भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ाया। विद्यार्थी मेधा, प्रतिभा के साथ देश के सामने विद्यमान चुनौतियां और जरूरतों का भी ध्यान रखें और देश भक्ति के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हों।

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य
देश की महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर

मुरैना, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना स्थित देवरी घड़ियाल केंद्र से चंबल नदी में 10 घड़ियालों (9 मादा और 1 नर) को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वन्य जीव पर्यटन का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुरैना क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हम मध्यप्रदेश के वनों में सभी प्रकार के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सक्षम हैं और इस दिशा में हमारे प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि चंबल अभयारण्य हमारे देश की प्राकृतिक संपदा है। यहां दुर्लभ प्रकार की प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश हमेशा से जैव विविधता के लिये महत्वपूर्ण प्रजातियों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिये तत्पर रहा है। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में वन पर्यटन की अनंत संभावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र सहित संपूर्ण प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। चंबल अभयारण्य में सिर्फ घड़ियाल ही नहीं, डॉल्फिन के भी पुनर्वास की प्रबल संभावना है। वन विभाग के माध्यम से इस दिशा में भी काम जारी है।

/संक्षिप्त खबर/

स्थानीय निकाय अपने अधिकारों से करें जनकल्याण के कार्य

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स मध्यप्रदेश इकाई की बैठक को वर्चुअल संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों को अधिकार संपन्न बनाया गया है। नगरीय निकाय और अन्य स्थानीय निकाय अपने अधिकारों और शक्तियों का उपयोग करते हुए जनकल्याण के कार्य बेहतर रूप से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान की सफलता इस बात का बेहतर उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकाय राज्य सरकार की भावना को और अधिक मजबूती प्रदान करें। नगरीय निकाय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें इसके लिए सब मिलकर प्रयास करें और आय के स्रोत बढ़ाएं। नगरीय निकाय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे तो विकास को और नई गति दी जा सकेगी।

भीतर के पृष्ठों पर

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा** - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

सिंचाई रकबे को एक करोड़ हेक्टेयर ले जाने का प्रयास हो पूर्ण - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे को वर्ष 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं में निर्माण गतिविधियों का संचालन समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ-2028 में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ओंकारेश्वर दर्शन के लिए भी जाएगी। अत: ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के दोनों तटों पर घाट निर्मित किए जाएं।

सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

बैठक में बड़ादेव संयुक्त माइक्रो सिंचाई परियोजना अंतर्गत टेरिया नाला बांध, सानेर बांध और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के निर्माण कार्य, सोण्डवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, धार उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, बहोरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-धांदला-सरदारपुर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण, महेश्वर-जानापाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई।

सिंहस्थ-2028
प्रबंधन में एआई सहित अद्यतन तकनीकों का उपयोग हो

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ-2028 के प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहित अद्यतन तकनीकों के उपयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ-2028 को श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय अनुभूति बनाने के उद्देश्य से आवागमन, पार्किंग, स्नान, भीड़ प्रबंधन, आवास, स्वच्छ पेयजल, भोजन, चिकित्सा सुविधा और अपशिष्ट प्रबंधन सहित सभी पहलुओं के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। व्यवस्थाओं के संचालन में सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहित सभी अद्यतन तकनीकों का उपयोग हो।

जीआईएस में प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे मध्यप्रदेश की विभिन्न औद्योगिक नीतियां

एक नजर में

- जीआईएस में 60 से अधिक देश के प्रतिभागी शामिल होंगे।
- जिम्बाब्वे के उप मंत्री सहित 10 देशों के राजदूत शामिल होंगे।
- 8 देशों के उच्चायुक्त, 7 देशों के काउंसलेट जनरल सहित कुल 133 विदेशी प्रतिभागी शामिल होंगे।
- देश के प्रमुख उद्योगपतियों सहित भारत की अग्रणी कंपनियों के 300 से अधिक अध्यक्ष, एमडी और सीईओ भी प्रतिभागी के रूप में शामिल होंगे।

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन में 24 एवं 25 फरवरी को भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए गठित शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय जीआईएस का शुभारंभ कर प्रदेश की सभी नवीनतम औद्योगिक नीतियों की लॉन्चिंग भी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आईएस परिसर में स्थापित एमपी एक्सपीरियंस जोन का अवलोकन भी करेंगे। इस जोन में इमर्सिव डिजिटल वॉक-थ्रू के रूप में मध्यप्रदेश की विरासत, अब तक की प्रगति और भावी आकांक्षाओं का समन्वित संयोजन एवं प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीआईएस को भव्य, सुव्यवस्थित और परिणामदायी बनाने के लिए सभी विभाग बेहतर समन्वय एवं सामंजस्य से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसीलिए आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारियां व्यापक स्तर पर की जायें।

देश-विदेश के निवेशक विशेष अतिथि

मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि जीआईएस में देश-विदेश से आने वाले निवेशक हमारे विशेष अतिथि हैं, इसलिए उनका अभिनंदन विशुद्ध भारतीय परम्परा से हो। इन दो दिनों को स्मरणीय बनाने के लिए मध्यप्रदेश की संस्कृति, सत्कार परम्परा और विभिन्न कला उत्पादों सहित यहां के खान-पान, व्यंजन आदि का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाए, जिससे निवेशक दो दिन मध्यप्रदेश में रहने का शानदार अनुभव लेकर जाएं।

15 फरवरी

छात्र अब आईटीईपी में स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स में कर सकेंगे बीएड

• राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने एक वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी दी। 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से इसे शुरू करने की तैयारी है। चार वर्ष का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) अभी भारत के 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है। इन संस्थानों में छात्र अपनी पसंद के विषय में बीएड करते हैं। अब आईटीईपी से योगा एजुकेशन, आईटीईपी फिजिकल एजुकेशन, आईटीईपी संस्कृत, आईटीईपी परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स जोड़े जाएंगे। उल्लेखनीय है कि आईटीईपी एक चार वर्षीय दोहरी सामग्री स्नातक डिग्री (डुअल इंटीग्रेटेड प्रेजुएशन डिग्री) है।

• भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई) ने (कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग (सीएमए कोर्स) के जून सत्र के लिए परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। फाउंडेशन परीक्षा 14 जून को आयोजित की जाएगी। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं 11 जून से शुरू होंगी। जून फाउंडेशन परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। सीएमए फाउंडेशन का परिणाम 8 जुलाई को घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। वहीं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंटरमीडिएट और फाइनल ग्रुप की परीक्षाएं 11 से 18 जून तक होंगी। सीएमए फाइनल परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सीएमए इंटरमीटिएट कोर्स परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।

16 फरवरी

सरकार का हस्तक्षेप कम करने के लिए विनियमन आयोग होगा गठित

• प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि शासन के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप को कम करने के लिए विनियमन आयोग का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जन विश्वास के माध्यम से, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना है कि समाज में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। इसके लिए सरकार विनियमन आयोग का गठन भी करने जा रही है। सरकार ने निवेश और दक्षता के लिए परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष सहित कई नए क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोले हैं।

• गाजा में युद्धविराम समझौते की शर्त के अनुसार हमास ने तीन और इजरायली बंधकों को मुक्त किया। इसके बदले में इजरायल ने 369 फलस्तीनी कैदी रिहा किए। इन बंधकों को गाजा के खान यूनिस में हमास के हथियारबंद लड़ाकों ने रेडक्रास के अधिकारियों को सौंपा, जहां से इजरायली सैनिक उन्हें इजरायल लाए। इसके कुछ देर बाद फलस्तीनी कैदियों को लेकर इजरायल की बसें वेस्ट बैंक पहुंचीं।

17 फरवरी

भारतीय नागरिकों को यूएई ने दी वीजा ऑन-अराइवल सुविधा

• संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-ऑन-अराइवल

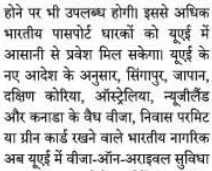

सुविधा का विस्तार किया है। अब भारतीय यात्रियों को यह सुविधा छह और देशों के वैध वीजा, निवास परमिट या ग्रीन कार्ड होने पर भी उपलब्ध होगी। इससे अधिक भारतीय पासपोर्ट धारकों को यूएई में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। यूएई के नए आदेश के अनुसार, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के वैध वीजा, निवास परमिट या ग्रीन कार्ड रखने वाले भारतीय नागरिक अब यूएई में वीजा-ऑन-अराइवल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यूएई में वीजा-ऑन-अराइवल सुविधा का लाभ उठाने के लिए भारतीय नागरिकों के पास सामान्य पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैधता आगमन की तारीख से कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। यूएई ने भारतीय यात्रियों के लिए तीन प्रकार के वीजा विकल्प पेश किए हैं, जिनके लिए नाममात्र शुल्क लिया जाएगा।

• भारत में 29,500 से अधिक ड्रोन एवं मानव रहित उड़ान उपकरण पंजीकृत किए गए हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में बताया कि इनमें से सर्वाधिक ड्रोन 4882 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पंजीकृत किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 4588 और 4132 ड्रोन पंजीकृत किए गए हैं।

18 फरवरी

ईएसबी ने बदला फॉर्मूला, नई पद्धति से बनेंगे परीक्षा परिणाम

• मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) ने भर्ती परीक्षाओं के

नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में बदलाव किया है। अब परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने के लिए नॉर्मलाइज्ड ईक्वी पर्सेंटाइल (एनईपी) स्केलिंग टेक्निक अपनाई जाएगी। यह फॉर्मूला जनवरी 2025 से लागू होगा और सभी आगामी परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जाएगा। अब जिन परीक्षाओं का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जाएगा, उनके परिणाम नए फार्मूले के आधार पर तैयार किए जाएंगे। एक पाली में एक से अधिक विषय के प्रश्नपत्र देने वाले आवेदकों के परिणाम भी इसी पद्धति से तय किए जाएंगे। एक चरणीय परीक्षा के लिए प्रत्येक पाली में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या और उनके स्कोर के आधार पर पर्सेंटाइल निकाला जाएगा। फिर सभी पालियों के पर्सेंटाइल स्कोर को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी।

• रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ की घटना के चलते रेल एवं रेलवे स्टेशनों में भीड़ प्रबंधन के लिए मैनुअल तैयार करने का निर्णय लिया है। साथ ही रेल आने के समय भगदड़ को रोकने के लिए देश के 60 प्रमुख स्टेशनों के बाहर होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। इन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाकर स्टेशन के अंदर यात्रियों की भीड़ पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके अंतर्गत उनके ट्रेन के प्रस्थान के अनुसार ही प्लेटफार्म पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि रेलवे ने प्रयागराज के आसपास के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले रेलवे स्टेशनों पर भी तत्काल प्रभाव से सतर्कता बढ़ाई है।

19 फरवरी

जनरल टिकटों पर भी लिखे जाएंगे ट्रेनों के नाम और नंबर

• रेलवे मंत्रालय ने पर्व-त्योहारों और विशेष अवसरों पर रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक

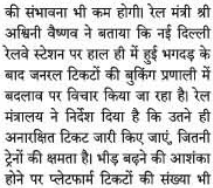

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई उपायों पर विचार किया है। इनमें अनारक्षित टिकटों पर ट्रेनों के नाम और नंबर दर्ज करने का प्रस्ताव शामिल है। इससे यात्री निर्धारित समय से पहले प्लेटफार्म पर नहीं जा सकेंगे और अंतिम समय में प्लेटफार्म बदलने की संभावना भी कम होगी। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ के बाद जनरल टिकटों की बुकिंग प्रणाली में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि उतने ही अनारक्षित टिकट जारी किए जाएं, जितनी ट्रेनों की क्षमता है। भीड़ बढ़ने की आशंका होने पर प्लेटफार्म टिकटों की संख्या भी सीमित करने के लिए कहा गया है।

• मैक्सिको सरकार ने गूगल को चेतावनी दी है कि अगर उसने अपने मैप में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी किया तो वह उसके खिलाफ अदालत जाएगी। गूगल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलने वाला है। मैक्सिको ने गूगल को पत्र लिख कर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश अमेरिका के क्षेत्रीय जल में या तट से 22 नॉटिकल माइल तक ही वैध है।

20 फरवरी

अगले वर्ष से दो बार होंगी दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं

• केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2026 से दसवीं के लिए वर्ष में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई 2026-27 के सत्र से संबंधित 260 विदेशी स्कूलों के लिए एक वैश्विक पाठ्यक्रम भी तैयार करेगा। नई प्रणाली के तहत छात्रों के पास वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने और अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर को बनाए रखने का विकल्प होगा। सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह योजना विद्यार्थियों में परीक्षा के दबाव को कम करने और छात्रों को प्रदर्शन बेहतर बनाने का अवसर देगी।

• भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को बीमा-एएसबीए सुविधा लागू करने का निर्देश दिया है। इस सुविधा से पॉलिसीधारक अपने बैंक खाते में प्रीमियम राशि ब्लॉक कर सकते हैं, जो पॉलिसी जारी होने पर ही डेबिट होगी। इरडा के अनुसार, प्रीमियम का भुगतान तभी होना चाहिए जब बीमा कंपनी प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सूचित करे। यूपीआई-ओटीएम फीचर से धनराशि ब्लॉक की जा सकती है।

21 फरवरी

पीएम केयर्स योजना के तहत दी जाएगी मुफ्त कोचिंग

• केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत जाती और आय सम्बन्धी प्रतिबंधों को खत्म किया। केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स योजना के माध्यम से छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करने की एक नई पहल शुरू की है। जिसका उद्देश्य छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना में ऐसे छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग का प्रावान है, जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत, जेईई, नीट, यूपीएससी व राज्य लोक सेवा

आयोगों द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए कोचिंग मिलेगी। बैंकों, बीमा कंपनियों के अधिकारी-ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग दी जाएगी।

• टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 जारी की। इसमें अकादमिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के आधार पर विश्वभर के शीर्ष विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। सूची में भारत के चार विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। भारत में बेंगलुरु का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शीर्ष पर है। इसके साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, आईआईटी मद्रास और ओडिशा का एजुकेशन ओ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। इस वर्ष 38 देशों और क्षेत्रों के 300 संस्थानों को रैंकिंग दी गई है। इनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 14वें साल वैश्विक स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में सामने आया है। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी (एमआईटी) है। चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी आठवें स्थान पर है, जबकि जापान का टोक्यो विश्वविद्यालय 10वें स्थान पर है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित
फोटो : गूगल से साभार)

TRANSNATIONAL KNOWLEDGE SOCIETY'S
SHIVAJIRAO KADAM GROUP OF INSTITUTIONS
An ISO 9001 : 2015 Certified Institute
Tillora Khurd, Near Ralamandal, Indore (M.P)
APPOINTMENT
SHIVAJIRAO KADAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT
An UGC Autonomous Institute | NAAC Accredited Grade 'A'
Professor / Associate Professor / Assistant Professor / Lab Technician
For B.Tech (CSE / AIML / DS / ME / EC / CE / English / Chemistry / Math.)
For MBA (HR / Finance / Marketing / IT / Production / Business Analytics)
Eligibility : As per UGC / AICTE / RGPV (Statue 30) / DAVV Norms (Code 28)
SHIVAJIRAO KADAM INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION & RESEARCH
Professor / Associate Professor / Assistant Professor / Lab Technician
(Pharmacology / Pharmaceutics / Pharmaceutical Chemistry / Pharmaceutical Analysis / Pharmacognosy / QA)
Eligibility : As per PCI / RGPV Norms (Statue 30)
COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES - ATC
Professor / Associate Professor / Assistant Professor (For BBA & B.Com)
(Commerce / Management / Hindi / English / Computers)
Eligibility : As per UGC / AICTE / DAVV Norms (Code 28)
TRANSNATIONAL SCHOOL OF LAW
Principal / Professor / Associate Professor / Assistant Professor
For: BA LLB (Hons.) / BBA LLB (Hons.) / LLB (Hons.)
Management / Economics / History / English / Political Science
Eligibility : As per UGC / BCI / DAVV (Code 28 Norms)
ALSO LOOKING FOR
Visiting Faculty as per NEP / Registrar / Office Staff / Marketing Executives / Librarian / TPO
Interested candidates may send applications along with the latest CV to the Principal at hr@skitm.in within 15 days and may contact on
0731 2995585, 9770907100
ANIL PUB.
R-50612/2025

SWAMI VIVEKANAND GROUP OF INSTITUTIONS
Approved by AICTE, Affiliated to RGPV, DAVV & PCI, Govt. of M.P)
Khandwa Road, Near Old Toll Naka, Indore 452 020 (M.P)
Ph.: 07324-405000
APPLICATIONS INVITED FROM CANDIDATE OF ENGINEERING, PHARMACY & MANAGEMENT
PRINCIPAL | PROFESSOR | ASSOCIATE PROFESSOR
ASSISTANT PROFESSOR
CS, EC, EX, IT, ME, CE, MBA & Pharmacy
Qualification & Experience as per AICTE Norms.
Selection will be under DAVV college code 28 and RGPV college code 30
Note: Apply within 10 days at career@svceindore.ac.in
ANIL PUB.
R-50613/2025

वर्ष 42, अंक 09 24.02.2025 से 02.03.2025
रोज़गार और निर्माण
www rojgaraurnirman.in

• प्रबंध संचालक - डॉ. सुधाम खाड़े
• सम्पादक - रंजना चितले
• प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
• प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
• आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
• वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इससे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

मध्यप्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने 'मध्यप्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) पॉलिसी 2025' लॉन्च की है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने और राज्य को एक डिजिटल एवं तकनीकी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया विजन को गति देने में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में इस नीति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा मंच मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समिट का 24 फरवरी को शुभारंभ करेंगे, जिससे मध्यप्रदेश का निवेश परिदृश्य और भी मजबूत होगा। दुनिया भर के निवेशकों, उद्योगपतियों और नीति-निर्माताओं के समक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस नीति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे, जिससे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के क्षेत्र में राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। इस समिट से जीसीसी के लिये बड़ी संख्या में निवेश प्रस्तावों की उम्मीद है, जिससे राज्य का आर्थिक परिदृश्य बदल जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स वे केन्द्र हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने मुख्यालय से अलग-अलग देशों में स्थापित करती हैं। इनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपने ऑपरेशंस को सुचारु रूप से चलाना और अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाना होता है। इन केन्द्रों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, वित्तीय सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ग्राहक सहायता जैसी सेवाएं दी जाती हैं। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीसीसी हब बन चुका है, जहां 1600 से अधिक जीसीसी कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश इस सेक्टर में अपनी भागीदारी को तेजी से बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह नीति विशेष रूप से आईटी, वित्त, इंजीनियरिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने पर केन्द्रित है और राज्य का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से मध्यप्रदेश देश के सबसे उभरते हुए निवेश केन्द्रों में शामिल हो चुका है। उनके नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, आईटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को इस नीति के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी बनाया है, जो कंपनियों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। राज्य में जीसीसी को तेजी से स्थापित करने के लिए एक विशेष नीति क्रियान्वयन इकाई बनाई जा रही है, जो प्रोत्साहनों के आवंटन, परियोजनाओं की स्वीकृति और अनुपालन निगरानी का कार्य करेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेशकों को समय पर सभी सुविधाएं मिलें और वे राज्य में अपने प्रोजेक्ट्स को शीघ्र शुरू कर सकें। मध्यप्रदेश में जीसीसी के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों में राज्य के आईटी, आईटीईएस निर्यात में तीन गुना वृद्धि हुई है और वार्षिक वृद्धि दर 43 प्रतिशत है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहर तेजी से आईटी और ईएसडीएम हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। राज्य में 300 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां से हर साल 50 हजार से अधिक टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट निकलते हैं। निवेशकों के लिए किफायती बिजनेस ऑपरेशन, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र और सरल नियामकीय प्रक्रियाएं इस नीति को और अधिक प्रभावी बना रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर है, जो यह साबित करता है कि राज्य में निवेशकों के लिए एक अनुकूल माहौल मौजूद है।

मध्यप्रदेश की जीसीसी नीति-2025 एक परिवर्तनकारी पहल है, जो भारत को वर्ष 2030 तक 110 बिलियन डॉलर के जीसीसी बाजार के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इनोवेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रोत्साहनों पर केंद्रित यह नीति राज्य को वैश्विक कंपनियों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनाएगी, जहां वे अपने जीसीसी ऑपरेशंस को स्थापित और विस्तारित कर सकेंगी। इस नीति के क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश नवाचार, टेक्नोलॉजी और रोज़गार सृजन के नए युग में प्रवेश करेगा, जिससे राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोज़गार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

पश्चिम एशिया में आर्थिक सहयोग, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और व्यापार को बढ़ावा देगा I2U2 समूह

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पहली अमेरिका यात्रा पर गये। इस यात्रा में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नये समूह के निर्माण पर सहमति प्रदान की। यह समूह चार देश भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका मिलकर बना रहे हैं। इस समूह को I2U2 नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस पहल के बाद भारत-अमेरिका के रणनीतिक सहयोग को और मजबूती मिलने की संभावना है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से पश्चिम एशिया (मिडिल) में आर्थिक सहयोग, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और व्यापार को बढ़ावा देना है। उल्लेखनीय है कि I2U2 की स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था। जिसमें इन चार देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। विदेशी मामलों के जानकारों के अनुसार I2U2 के तहत भारत और इजरायल की कृषि तकनीकों, अमेरिका की पूंजी और यूएई के वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल कर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की योजना है। यही नहीं समूह सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और सस्टेनेबल एनर्जी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। इसके तहत भारत को एक बड़ा हब बनाने की योजना है, जहां हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात किया जाएगा। समूह के चारों देश एक-दूसरे की अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, यूएई, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स में भारी निवेश कर रहा है जबकि अमेरिका और इजराइल रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग I2U2 की तुलना क्वाड से कर रहे हैं जबकि दोनों समूहों के उद्देश्य अलग-अलग है। क्वाड एक रणनीतिक सुरक्षा समूह है, जिसमें चार देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है।

- विकास तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं)

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट : मध्यप्रदेश नया इतिहास रचने की ओर

उद्यमिता के वैश्विक स्वरूप से ही भारत सोने की चिड़िया बना था

संसार के प्राचीनतम भू-भागों में से ये एक मध्यप्रदेश की धरती केवल मानव सभ्यता के विकास में ही अग्रणी नहीं रही, उद्यमिता विकास में भी अग्रणी रही है। मध्यप्रदेश के ख्याति प्राप्त उत्पाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। समय की गति से भले वह साख प्रभावित हुई हो लेकिन अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को विश्व में पुनः उसी स्थान पर प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया है। 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इसी दिशा में एक नया इतिहास रचने जा रही है।

भारत का इतिहास ऊन्नति और उज्ज्वलता से भरा है। जीवन की ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें भारत विश्व प्रसिद्ध न रहा हो। ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान से विश्वगुरु की उपाधि थी तो उद्यमिता, शिल्प और कला, कौशल से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत में सोने की खदानें नहीं थीं और न सोना बनाने के कारखाने थे। फिर भी सोने की चिड़िया नाम मिला। भारत को यह सम्मान उद्योग व्यवसाय से अर्जित संपत्ति के कारण ही मिला था। कुटीर, शिल्प, कौशल से लेकर विशाल औद्योगिक उत्पादक भी भारत रहा है। भारतीय उत्पाद से भरे जहाज पूरे विश्व में जाते थे और बदले में स्वर्ण भंडार आता था। इससे भारत इतना समृद्ध हुआ कि सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। इतिहास में जहां तक दृष्टि जाती है भारत में उद्योग व्यापार का उल्लेख मिलता है। उद्योग व्यापार के द्वारा समृद्धि अर्जित करने का संदेश वेदों में भी है। चारों वेदों में अनेक ऐसी ऋचाएं हैं जिनमें वाणिज्य व्यवसाय से समृद्धि अर्जित करने के संदेश हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के इसी वैभव को पुनर्प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया है। इसके लिये उन्होंने वर्ष 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है। ताकि भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी दिवस तक पुनः आर्थिक और सामरिक रूप से विश्व में सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन सके। मोदी जी के इस संकल्प के अनुरूप ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के विकास की रूपरेखा तैयार की है। विकास का एक ऐसा स्वरूप जो अपनी विरासत के साथ वैश्विक भी हो। इसके लिये आवश्यक है कि मध्यप्रदेश अपनी वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुये और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हुये ऐसे उत्पाद में अग्रणी बने जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। यह तभी संभव है जब मध्यप्रदेश ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कार और अनुसंधान के साथ औद्योगिक विकास के भी शिखर पर पहुंचे। क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स समिट के साथ अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्यप्रदेश की इसी आवश्यकता के अनुरूप है। डॉ. मोहन यादव भी मध्यप्रदेश को औद्योगिक विकास की उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंचाने के प्रयत्न कर रहे हैं। औद्योगिक विकास और निर्यात में भी मध्यप्रदेश इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद वाकणकर जी ने मौर्यकाल और गुप्तकाल के शिल्प और लोह उत्पाद खोजे हैं जो उज्जैन के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बाबर के आक्रमण के समय चंदेरी एक समृद्ध व्यापारिक केन्द्र रहा है, तो लोकमाता अहिल्याबाई के समय में महेश्वर साड़ी विश्व प्रसिद्ध रही है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, पार्वती और कालीसिंध नदियों के किनारे शिल्प, कौशल, कपास और धातु आधारित उद्योगों का वर्णन मिलता है। यह उत्पाद नावों द्वारा समुद्र तट के बंदरगाहों पर जाया करते थे। पांच सौ वर्ष पहले मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत सिरोंज में ऐसे बाजार के प्रमाण मिले हैं जहां चार मंजिला दुकानें थीं अर्थात हाथी पर बैठे-बैठे भी सामान क्रय किया जा सकता था अथवा ढुलाई के लिये हाथी पर भी सामान लादा जा सकता था। मध्यप्रदेश में मालवा का कपास, नर्मदा पट्टी की तुअर दाल और विदिशा जिले का शरबती गेहूं, बासौदा का पत्थर, विन्ध्य का चूना पत्थर आदि की मांग आज भी पूरे विश्व में है।

मध्यप्रदेश में औद्योगीकरण का अभियान

मध्यप्रदेश की इस औद्योगिक प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिये ही देश और विदेश के उद्योगपतियों को निवेश के लिये आमंत्रित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार इस निवेश में दो प्रकार का ध्यान रखने जा रही है एक तो मध्यप्रदेश का स्थानीय उत्पाद प्रतिष्ठित हो और दूसरा रोज़गार के अवसर सृजित हों। इसके लिए मुख्यमत्री डॉ. मोहन यादव ने इन्वेस्टर्स समिट का मानो एक अभियान ही चलाया हुआ है। मध्यप्रदेश में तीनों प्रकार की इन्वेस्टर्स समिट हो रही हैं। रीजनल इन्वेस्टर्स समिट भी और नेशनल इन्वेस्टर्स समिट भी। ऐसी दोनों प्रकार की समिट के आयोजन हो चुके हैं और अब ग्लोबल समिट आयोजित की जा रही है। अनुमान है इस समिट में पचास से अधिक देशों की लगभग सौ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की ओर से निवेशक भाग लेंगे। जबकि भारत के लगभग प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर से इस इन्वेस्टर्स समिट में आने की सहमति मिल चुकी है।

24 एवं 25 फरवरी को भोपाल में हो रही इस समिट में अमेरिका, इग्लैंड, जापान, जर्मनी, रूस, चीन और फ्रांस जैसे दुनिया के लगभग पचास देशों से इन्वेस्टर्स के भोपाल आने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं जापान, जर्मनी और यू के जाकर निवेशकों को आमंत्रित भी किया है। अनुमान है इसमें देश विदेश के कुल पन्द्रह हजार से अधिक निवेशक अथवा उनके प्रतिनिधि आ सकते हैं।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने निवेशकों को मध्यप्रदेश की विशेषताएं समझाने के लिये पूरी तैयारी कर रखी है। जिन विषयों पर निवेशकों को अवगत कराया जाना है उनमें रिन्युएबल एनर्जी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, ट्रूरिज्म, माइनिंग, एमएसएमई एंड स्टार्टअप, अर्बन डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश की इस संभावना से निवेशकों को अवगत कराने के लिये डेस्क बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिये मध्यप्रदेश पर्यटन निगम ने अभी से टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी है। ताकि निवेशकों को प्रजेंटेशन के दौरान ही कोई विशिष्ट स्थल पसंद आता है और उस लोकेशन का विजिट करना चाहे तो तुरन्त उन्हें विजिट कराने ले जाया जा सके। मध्यप्रदेश पर्यटन निगम ने ऐसी 25 लोकेशन निर्धारित की हैं इन सभी स्थानों पर होटल, रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर और ट्रूरिज्म एक्टिविटी से जुड़ी अन्य गतिविधि आरंभ की जा सकती हैं। ये लोकेशन जबलपुर, मंदसौर, धार, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, नीमच, बैतूल, रायसेन, बुरहानपुर, शाजापुर, शहडोल, विदिशा और अलीराजपुर जिलों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश के अन्य स्थलों के प्रजेंटेशन में उस क्षेत्र विशेष की सुविधा, भूमि और कच्चे माल की उपलब्धता तथा ट्रांसपोर्टेशन आदि के बारे में भी अवगत कराया जायेगा। इन स्थलों के स्पॉट निरीक्षण की व्यवस्था भी की गई है। समिट के लिये एक मुख्य डोम तैयार किया गया है। डोम में 40 से ज्यादा बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य अतिथियों का संबोधन सभी आगन्तुक सुन सकें।

निवेशकों की सुविधा के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कुछ नियमों का सरलीकरण भी किया है और कुछ अनुमतियों की बाध्यता कम की है। एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिये अब तक लगभग तीस से अधिक अनुमतियों की आवश्यकता होती थी। अब राज्य सरकार ने इन्हें घटाकर केवल दस कर दिया है। इसके लिये भी अलग-अलग विभागों के चक्कर काटना नहीं पड़ेंगे। राज्य सरकार एक ऐसी नोडल डेस्क बना रही है जहां से ये सभी अनुमतियां सरलता से मिल सकें। निवेशकों को सुविधा देने तथा क्षेत्रीय विशेषताओं से अवगत कराने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए हैं। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश में 15 से अधिक आईटी पार्क हैं। मध्यप्रदेश में देश की 50 से ज्यादा बड़ी आईटी और आईटीईएस इकाइयां पहले से ही स्थापित हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त यहां का वातावरण भी निवेशकों के लिये बहुत उपयुक्त है।

मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं

विश्व में हो रही विकास की इस दौड़ में सहभागी होने के लिये मध्यप्रदेश को एआई एवं आईटी की दिशा में स्वयं को सक्षम बनाना होगा। मध्यप्रदेश सरकार ने समय की इस आवश्यकता को प्राथमिकता में रखकर निवेशकों को आमंत्रित किया है। इन दोनों विषयों पर आरंभिक अनौपचारिक बातचीत भी हो चुकी है। आशा की जा रही है कि इस समिट में आईटी और एआई से संबंधित इकाई निर्माण के करार पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर दे रहे हैं। युवाओं का भविष्य उनकी स्किल पर ही निर्भर करेगा। आधुनिकीकरण को रोका नहीं जा सकता और न एआई से दूर रहा जा सकता। ये दोनों बाते विश्व में प्रगति का आधार बनने वाले हैं। समय की इस आवश्यकता के अनुरूप ही मध्यप्रदेश सरकार ने इस ग्लोबल समिट की तैयारी की है। सरकार की इस तैयारी को देखकर आशा की जा रही है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश के करार होने का कीर्तिमान बनेगा और देश के विकसित प्रांतों की सूची में मध्यप्रदेश अग्रणी प्रदेश बनेगा।

रमेश शर्मा

(लेखक स्तम्भकार हैं)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

(अनुसूची–'ए' मिनिरत्न श्रेणी–1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)
विज्ञापन संख्या 01/2025/उ.क्षे.
उत्तरी क्षेत्र में गैर–कार्यपालक संवर्ग के पदों के लिए भर्ती

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्र द्वारा चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मूल निवासी पात्र उम्मीदवारों से उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न हवाईअड्डों के लिए वरिष्ठ सहायक (राजभाषा), वरिष्ठ सहायक (लेखा), वरिष्ठ सहायक (इलेक्ट्रॉनिक्स) और कनिष्ठ सहायक (अग्निशमन सेवा) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थी केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट (**www-aai-aero → कैरियर**) पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से जमा, आवेदन और शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि	04.02.2025
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	05.03.2025

1. पदों का ब्योरा

पोस्ट कोड	पद का नाम और पद का स्तर	रिक्तियों और आरक्षण की संख्या											
		कुल	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी (एनसीएल)	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी				एक्स–एसएम*	एक्स अग्निवीर**
								श्रेणी (क)	श्रेणी (ख)	श्रेणी (ग)	श्रेणी (डी–ई)		
01	वरिष्ठ सहायक (राजभाषा), एनई–6 स्तर	04	01	--	01	01	01	01	01	--	--	--	--
02	वरिष्ठ सहायक (लेखा), एनई–6 स्तर	21	10	03	01	05	02	02	02	03	02	03	--
03	वरिष्ठ सहायक (इलेक्ट्रॉनिक्स), एनई–6 स्तर	47	22	08	02	11	04	--	--	--	--	07	--
04	कनिष्ठ सहायक (अग्निशमन सेवा) एनई–04 स्तर	152	63	28	07	39	15	--	--	--	--	22	15

***भूतपूर्व–एस.एम. के आरक्षण में दिव्यांग भूतपूर्व–एस.एम. तथा युद्ध में मारे गए भूतपूर्व–एस.एम. के आश्रितों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित 10 पद शामिल हैं।**

****इसके अलावा, भूतपूर्व अग्निवीरों को 10% का क्षैतिज आरक्षण केवल कनिष्ठ सहायक (अग्निशमन सेवा) पद के लिए लागू है।**

2. परिलब्धियां

(क) वेतनमान और स्तर – एनई–6 लेवल (वरिष्ठ सहायक) में 36,000–3%–1,10,000 रुपये–आईडीए पैटर्न

(ख) वेतनमान और स्तर – एनई–4 लेवल (जूनियर असिस्टेंट) में 31,000–3%–92,000 रुपये–आईडीए पैटर्न

मूल वेतन के अतिरिक्त, महंगाई भत्ता, मूल वेतन के 35% की दर से अनुलाभ, एचआरए और अन्य लाभ, जिसमें सीपीएफ, ग्रेच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, चिकित्सा लाभ आदि शामिल हैं, भाविप्रा के नियमों के अनुसार स्वीकार्य हैं।

2 आयु सीमा और आयु में छूट

अधिकतम आयु सीमा 05.03.2025 तक 30 वर्ष है और सरकारी मानदंडों के अनुसार आयु में छूट है।

3. शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

पोस्ट कोड	पद का नाम /स्तर	शैक्षणिक योग्यता
01	वरिष्ठ सहायक (राजभाषा), एनई–6 स्तर	स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर अथवा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर **अथवा** स्नातक स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में मास्टर डिग्री। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी / अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम और अनिवार्य / वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होना चाहिए। अर्थात यदि स्नातक स्तर पर हिंदी माध्यम है तो अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय होना चाहिए या अंग्रेजी माध्यम है तो हिंदी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय होना चाहिए। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हो साथ ही हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रमों अथवा प्रतिष्ठित संस्थानों सहित केंद्र/राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव । **योग्यता मानदंडों के अतिरिक्त, एमएस ऑफिस (हिन्दी) में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा ।** **अनुभवः संबंधित विषय में दो वर्ष (2) का संगत अनुभव।**
02	वरिष्ठ सहायक (लेखा), एनई–6 स्तर	स्नातक अधिमानतः बी.कॉम. एमएस ऑफिस में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा सहित। **अनुभवः संबंधित विषय में दो वर्ष (2) का संगत अनुभव।**
03	वरिष्ठ सहायक (इलेक्ट्रॉनिक्स), एनई–6 स्तर	इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलिकम्युनिकेशन/रेडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। **अनुभवः संबंधित विषय में दो वर्ष (2) का संगत अनुभव।**
04	कनिष्ठ सहायक (अग्निशमन सेवा) एनई–04 स्तर	क) 10वीं पास + मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल/अग्निशमन में 3 साल का स्वीकृत नियमित डिप्लोमा। **(या)** ख) 12वीं पास (नियमित अध्ययन)
	ड्राइविंग लाइसेंस	क) वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस; या ख) विज्ञापन की तिथि से कम से कम **एक वर्ष** पहले जारी किया गया वैध मध्यम वाहन लाइसेंस। या ग) विज्ञापन की तिथि से कम से कम दो वर्ष पहले जारी किया गया वैध लाइट मोटर वाहन लाइसेंस (एलएमवी)। उपर्युक्त (ख) और (ग) के मामले में, पदधारियों को अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पहले नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है। यदि वे हैवी–ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी, तब तक उन्हें स्थायी नहीं किया जाएगा और उनकी वेतन वृद्धि भी रोक दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, दो साल के बाद और समय नहीं दिया जाएगा और उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। **अस्थायी/ लर्निंग लाइसेंस स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

(शेष अगले पृष्ठ पर)

दिग्दर्शिका ट्रेनिंग कॉलेज

(भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एवं बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त)

आवश्यकता है

बी.एड./एम.एड. विशेष शिक्षा (बौद्धिक दिव्यांगता)
पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के परिनियम 28 के अनुसार
सहायक प्राध्यापको के पदो हेतु आवदेन आमंतित्र करता है।

सहायक प्राध्यापक- 3 पद विशेष शिक्षा (बौद्धिक दिव्यांगता)

योग्यता:- स्नाकोत्तर 55% अंक एवं एम.एड विशेष शिक्षा (बौद्धिक दिव्यांगता) 55% अंक

अंतिम तिथि: 17 मार्च 2025

AANUPAM PUBLICITY

दिग्दर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान
10, रोहित नगर फेस-1, बावडिया कला, भोपाल पिन कोड - 462039
E-mail : digdarshikabhopal@gmail.com
Ph-0755-2562611, 9826025606 (कार्य दिवस समय 10:30 से 05:00 बजे तक)

R-50610/2025

SHRI VAISHNAV INSTITUTE OF MANAGEMENT & SCIENCE, INDORE

Formerly known as Shri Vaishnav Institute of Management, Indore • Estd. -1987
Approved by AICTE, New Delhi and Affiliated to DAVV, Indore & RGPV, Bhopal (M.P.)
UGC - NAAC accredited 'A' Grade Institute
Scheme No. 71, Gumasta Nagar, INDORE-452 009, Ph.: 0731-2780011, 2789925
E-Mail: svimi@svimi.org

R E Q U I R E S

- **PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR AND ASSISTANT PROFESSOR**
  Finance/Marketing/ Business Analytics/QuantitativeTechniques/ Operations Management/ Human Resource Management/ Hospital Administration/ Foreign Trade/ Computer Science/ Chemistry/ Biotechnology and Bioinformatics.
  Eligibility: As per UGC/AICTE norms for all the positions.
  Salary: As per UGC norms
- **SOFT SKILLS TRAINER:** Master's Degree in Management with first class having minimum five years experience and trained faculty having rich experience in grooming the students for a successful career.
- **LAB TECHNICIAN (COMPUTER):** BCA or B.Sc. (CS) or Graduate in any discipline with PGDCA from UGC recognized universities or DOEACC (O-Level) with minimum two years experience.
- **LAB TECHNICIAN (MICROBIOLOGY):** Bachelor's Degree in relevant subject or equivalent grade from recognized University/ Institute or post graduate diploma or equivalent grade from recognized institute with 2 years experience.

Salary is not a constraint for deserving candidate

Note: Applications of the candidates applied earlier will not be considered.

Candidate will apply in prescribed format by downloading the application form from Institute's website and duly filled form with all testimonials to be submitted in hard copy to the Institute address within 10 days of publication of advertisement. Also, mail your latest CV on **recruitments@svimi.org**

R-50611/2025

deepak

SHRI UMIYA GIRLS COLLEGE

(Approved by Govt.of MP & Affiliated to D.A.V.V. Indore)
Maheshwar Road Mandleshwar, Dist. Khargone(M.P.)

Requires

Professors, Associate Professors, Asst. Professors

1. Maths	02	8. Computer Science	02
2. Physics	01	9. Biotechnology	02
3. Chemistry	02	10. Commerce	02
4. Zoology	02	11. Political Science	02
5. Botany	02	12. Sociology	02
6. Home Science	02	13. Computer Operator	01
7. Lab Technician	01	14. Sport Officer	01

▶ Qualification & Experience as per U.G.C. Norms. Apply within 10 days with full details & attested copies send to college Address and by Email.(Compulsory to Net/Ph.d.)

Email Id: sugc.mandleshwar@gmail.com
Cont. us. 8305932605, 8815379541

R-50609/2025

कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन)
लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र ग्वालियर (म.प्र.)

दूरभाष- 0751-4008851, E-mail : apdpiugwalior@gmail.com

निविदा सूचना क्रमांक : 02/2025/सा./एपीडी/ **ग्वालियर, दिनांक : 10.02.2025**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रित की जाती है।

क्र.	ऑनलाइन निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनु. लागत लाख में	अमानत राशि रु.	निविदा फार्म का मूल्य रु. में	कार्य पूर्ण करने के लिये समय
1.	2025_ PWPIU_ 401648_1	जिला गुना के अन्तर्गत परफॉरमेन्स गारंटी के कार्य, बैलेंस वर्क के कार्य एवं राशि रु. 50.00 लाख से कम लागत की प्रशासकीय स्वीकृति के कार्य। **द्वितीय आमंत्रण**	गुना	90.00 लाख	90,000/-	10,000/-	12 माह
2.	2025_ PWPIU_ 401649_1	ग्राम मायापुर धनवाड़ी जिला गुना में शासकीय माध्यमिक स्कूल भवन निर्माण कार्य। **द्वितीय आमंत्रण**	गुना	118.47 लाख	1,18,467/-	12,500/-	08 माह
3.	2025_ PWPIU_ 401650_1	ग्राम सोनखरा जिला गुना में शासकीय माध्यमिक स्कूल भवन निर्माण कार्य। **द्वितीय आमंत्रण**	गुना	118.47 लाख	1,18,467/-	12,500/-	08 माह
4.	2025_ PWPIU_ 401651_1	आरोन जिला गुना में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भवन निर्माण कार्य। **प्रथम आमंत्रण**	गुना	107.68 लाख	1,07,680/-	12,500/-	08 माह
5.	2025_ PWPIU_ 401758_1	तहसील बानमोर, पोरसा एवं अम्बाह जिला मुरैना के अन्तर्गत परफॉरमेन्स गारंटी के कार्य, बैलेंस वर्क के कार्य एवं राशि रु. 50.00 लाख से कम लागत की प्रशासकीय स्वीकृति के कार्य। **द्वितीय आमंत्रण**	मुरैना	98.00 लाख	98,000/-	10,000/-	12 माह
6.	2025_ PWPIU_ 401742_1	ग्राम नयापुरा जिला गुना में शासकीय हाईस्कूल भवन निर्माण कार्य। **द्वितीय आमंत्रण**	मुरैना	119.65 लाख	1,19,650/-	12,500/-	12 माह
7.	2025_ PWPIU_ 401776_1	तहसील जौरा, कैलारस एवं सबलगढ जिला मुरैना के अन्तर्गत परफॉरमेन्स गारंटी के कार्य, बैलेंस वर्क के कार्य एवं राशि रु. 50.00 लाख से कम लागत की प्रशासकीय स्वीकृति के कार्य। **द्वितीय आमंत्रण**	मुरैना	98.00 लाख	98,000/-	10,000/-	12 माह
8.	2025_ PWPIU_ 401761_1	तहसील सतनबाड़ा जिला शिवपुरी में राज्य शिक्षा केन्द्र विभाग के अन्तर्गत केजीबीव्ही टाइप-III, 100 सीटर छात्रावास भवन निर्माण कार्य।	शिवपुरी	205.08 लाख	2,05,080/-	15,000/-	12 माह
9.	2025_ PWPIU_ 401796_1	तहसील बदरवास जिला शिवपुरी में आई.टी.आई. कॉलेज परिसर के अन्तर्गत मुख्य भवन में 01 नग एफ टाइप, 02 नग एच टाइप एवं 04 नग आई टाइप क्वार्टर का निर्माण कार्य।	शिवपुरी	822.79 लाख	8,22,790/-	10,000/-	18 माह
10	2025_ PWPIU_ 401846_1	तहसील बदरवास जिला शिवपुरी में राज्य शिक्षा केन्द्र विभाग के अन्तर्गत केजीबीव्ही टाइप-III, 100 सीटर छात्रावास भवन निर्माण कार्य।	शिवपुरी	205.08 लाख	2,05,080/-	15,000/-	12 माह

(1) निविदा से संबंधित डॉक्यूमेंट **website https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।
(2) निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन पोर्टल पर ऑनलाइन किये जावेंगे, समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशन नहीं किया जावेगा। (3) ऑनलाइन निविदा सब्मिट करने की **अंतिम दिनांक 25.02.2025**
(4) तकनीकी बिड खोलने का **दिनांक 27.02.2025**

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
जी-23104/50599/2025 **कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र ग्वालियर**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

	शारीरिक फिटनेस	**शारीरिक गठनः सुडौल (पुरुष और महिला दोनों)**	
	दृष्टि (पुरुष एवं महिला दोनों)	**दूर की दृष्टिः** बिना चश्मे के प्रत्येक आँख से 6/6 **नज़दीक की दृष्टिः** बिना चश्मे के प्रत्येक आँख से एन–5। (प्रत्येक आँख की दृश्य क्षमता का मूल्यांकन अलग–अलग होना है)। **रंग दृष्टिः** इशिहारा के चार्ट द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार सामान्य होनी चाहिए। **रतौंधीः** नहीं होनी चाहिए। **दृष्टि क्षेत्रः** टकराव परीक्षण द्वारा निर्धारित अनुसार प्रत्येक आँख में पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए। **अपवर्तक त्रुटिः** कोई अपवर्तक त्रुटि स्वीकार्य नहीं है। कार्यात्मक आवश्यकता के रूप में, कलर ब्लाइंडनेस और/या रतौंधी पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा।	
	सुनने की क्षमता	सामान्य	
	बोलने की क्षमता	सामान्य	
		पुरुष	**महिला**
	लंबाई	167 सेमी से कम नहीं ##	157 सेमी से कम नहीं ##
	छाती	विस्तार से पहले सामान्यः 81 सेमी ## न्यूनतम विस्तार 5 सेमी.	**लागू नहीं**
	वजन	55 किलो से कम नहीं	45 किलो से कम नहीं
	##	पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों को **लंबाई में 3 सेमी की छूट** (पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए) और छाती माप (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए) और वजन में आनुपातिक छूट बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। हालांकि, छाती का न्यूनतम विस्तार 5 सेमी (पुरुष उम्मीदवारों के लिए) होना चाहिए। किसी अन्य श्रेणी को कोई अन्य छूट नहीं दी जाएगी।	
	अयोग्यता	घुटने में दर्द, पैरों में झुकाव, भेंगापन, चपटे पैर, शारीरिक विकृति, कलर ब्लाइंडनेस और/या रतौंधी, दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित होना, कोई बड़ा ऑपरेशन जिसके कारण अग्निशमन सेवा में काम करने के लिए उसकी शारीरिक योग्यता दुर्बल हो गई हो, को अयोग्य माना जाएगा।	

विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया भाविप्रा की वेबसाइट **www.aai.aero → करियर → भर्ती देखें।**

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

(श्रेणी–"क", मिनी रत्न, उपक्रम)
(Schedule-"A", Mini Ratna, PSU)

Great Place To Work Certified

विज्ञा. सं.– 02/2025

अखिल भारतीय स्तर पर ई–2 ग्रेड में नियमित आधार पर विभिन्न विभागों में अनुभवी अभियंता/कार्यपालक की भर्ती

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, विद्युत क्षेत्र में अग्रणी और लाभ–कमाने वाला अनुसूची "ए" मिनी रत्न पीएसयू है। कंपनी की इक्विटी में एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी है। टीएचडीसीआईएल अखिल भारतीय स्तर पर ई–2 ग्रेड में नियमित आधार पर विभिन्न विभागों में अनुभवी अभियंता/कार्यपालक के रूप में नियुक्ति के लिए अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं अनुभव रखने वाले होनहार, समर्पित, परिणामोन्मुखी, ऊर्जावान और कर्मठ अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है

पदों का विवरण

ग्रुप–ए (हाइड्रो/थर्मल/कोल माइन्स प्रोजेक्ट के लिए)

पद कोड	पद का नाम	रिक्तियां					
		पद की सं.	अना.	ईडब्ल्यूएस	ओबीसी (एनसीएल)	एससी	एसटी
01	अभियंता (सिविल) ई–2 ग्रेड में	30	13	03	08	04	02
02	अभियंता (इलेक्ट्रिकल) ई–2 ग्रेड में	25	13	02	06	03	01
03	अभियंता (मैकेनिकल) ई–2 ग्रेड में	20	09	02	05	03	01
04	अभियंता (जियोलॉजी एंड जियो–टेक्निकल) ई–2 ग्रेड में	07	04	01	01	01	शून्य
05	अभियंता (पर्यावरण) ई–2 ग्रेड में	08	03	01	02	02	शून्य
06	अभियंता (माइनिंग) ई–2 ग्रेड में	07	04	01	01	01	शून्य
07	कार्यपालक (मानव संसाधन) ई–2 ग्रेड में	15	07	01	04	02	01
08	कार्यपालक (वित्त) ई–2 ग्रेड में	15	07	01	04	02	01

ग्रुप–बी (विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए)

पद कोड	पद का नाम	रिक्तियां					
		पद की सं.	अना.	ईडब्ल्यूएस	ओबीसी (एनसीएल)	एससी	एसटी
09	ई–2 ग्रेड में विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए अभियंता	02	02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विस्तृत जानकारी के लिए टीएचडीसीआईएल वेबसाइट में विस्तृत विज्ञापन को भली–भांति पढ़ लें।

ओबीसी (एनसीएल)/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्तियां सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित है।

योग्यता मानदंड:

01. **अभियंता (सिविल) ई–2 ग्रेड में:** भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उचित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ संगत विषय में पूर्णकालिक बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजी.)
संगत विषय – सिविल इंजीनियरिंग

02. **अभियंता (इलेक्ट्रिकल) ई–2 ग्रेड में:** भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उचित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ संगत विषय में पूर्णकालिक बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजी.)
संगत विषय – इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल (पावर)/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज/पावर इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन

03. **अभियंता (मैकेनिकल) ई–2 ग्रेड में:** भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उचित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ संगत विषय में पूर्णकालिक बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजी.)
संगत विषय – मैकेनिकल/मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग

04. **अभियंता (जियोलॉजी एंड जियो–टेक्निकल) ई–2 ग्रेड में:** मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों या समकक्ष या मास्टर डिग्री में समकक्ष ग्रेड के साथ एम.एससी. (जियोलॉजी)/एम.एससी. (एप्लाइड जियोलॉजी)/एम. टेक. (एप्लाइड जियोलॉजी)/जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेटेड एम.टेक./इंजीनियरिंग जियोलॉजी में एम.टेक. (स्नातक स्तर पर जियोलॉजी का अध्ययन किया होना चाहिए) पूर्णकालिक नियमित डिग्री।

05. **अभियंता (पर्यावरण) ई–2 ग्रेड में:** मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या भारत में उचित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ पर्यावरण इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक बी.ई./बी.टेक. के साथ एम.टेक.।

06. **अभियंता (माइनिंग) ई–2 ग्रेड में:** भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/उचित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ माइनिंग इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक डिग्री और डीजीएमएस से कोल में वैध प्रथम–श्रेणी मैनेजर्स सर्टिफिकेट।

07. **कार्यपालक (मानव संसाधन) ई–2 ग्रेड में:** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/उचित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ कार्मिक प्रबंधन (एचआर एक मुख्य या प्रमुख विषय के रूप में) में विशेषज्ञता के साथ पूर्णकालिक (नियमित) एमबीए या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ कार्मिक प्रबंधन/आईआर/श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ पीएम एंड आईआर/श्रम कल्याण में न्यूनतम 2 वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सामाजिक कार्य या एमएचआरओडी में मास्टर्स डिग्री।
वांछनीय योग्यता: एलएलबी

08. **कार्यपालक (वित्त) ई–2 ग्रेड में:** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान/भारतीय लागत लेखाकार संस्थान से सीए/सीएमए उत्तीर्ण।

09. **ई–2 ग्रेड में विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए अभियंता:** भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उचित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ संगत विषय में पूर्णकालिक बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजी)
संगत विषय – इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कन्ट्रोल/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन/मैकेनिकल
योग्यता पश्चात अनुभव के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विस्तृत विज्ञापन को देखें।

ऊपरी आयु सीमा: 30 वर्ष

चयन प्रक्रिया:

- यदि आवश्यक हो तो अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए प्रबंधन बहु–स्तरीय चयन प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसमें आवश्यकता के अनुसार आवेदन शॉर्टलिस्टिंग/स्क्रीनिंग (आवश्यक योग्यता, योग्यता पश्चात अनुभव के वर्षों की संख्या आदि के आधार पर), लिखित/कंप्यूटर–आधारित परीक्षण, व्यक्तिगत साक्षात्कार आदि शामिल हो सकते हैं।
- यदि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों की संख्या किसी भी पोस्ट कोड में 50 से कम है, तो उस पोस्ट कोड के लिए चयन प्रक्रिया में केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होगा।
- यदि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों की संख्या किसी भी पोस्ट कोड में 50 से अधिक है, तो उस पोस्ट कोड के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित/कंप्यूटर आधारित परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होंगे।

विस्तृत जानकारी के लिए टीएचडीसीआईएल वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन को भली–भांति पढ़ लें।

पारिश्रमिक पैकेज: ई–2 ग्रेड में अभियंता/कार्यपालक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान 50,000–3 प्रतिशत–1,60,000 (आईडीए) में न्यूनतम मूल वेतन रु. 50,000 पर रखा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा में रहेंगे और परिवीक्षा अवधि के सफल समापन पर अभ्यर्थियों को समान वेतन ग्रेड (अर्थात् वेतनमान 50,000–3 प्रतिशत –1,60,000 में ई–2 ग्रेड) में नियमित किया जाएगा।

कैरियर प्रगति: कृपया विस्तृत विज्ञापन देखें।

पंजीकरण शुल्क: रु. 600/– (केवल छह सौ रुपये) अना./ईडब्ल्यूएस/ओबीसी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करना होगा। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक/विभागीय उम्मीदवारों/डूब क्षेत्र/टीएचडीसी परियोजनाओं के परियोजना प्रभावित क्षेत्र के परिवारों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं है।

सामान्य जानकारी एवं निर्देश:

1. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में वर्णित योग्यता मानदंडों एवं अन्य मानकों को पूरा करते हैं।
2. सभी योग्यताएं भारतीय विश्वविद्यालय/एआईसीटीई उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संस्थान से पूर्णकालिक एवं नियमित आधार पर होनी चाहिए।
3. अपेक्षित आयु एवं अनुभव की गणना विज्ञापन की तिथि के अनुसार की जाएगी।
4. अनुभव के रूप में इंटर्नशिप/ट्रेनिंग/अप्रेंटिसशिप एवं टीचिंग अवधि की गणना नहीं की जाएगी।
5. पद के लिए आवेदन करते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्दिष्ट तिथियों पर ऊपर उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है और दिए गए विवरण सभी मामलों में सही हैं। यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रूप से रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी उपरोक्त में से कोई भी कमी पाई जाती है/पायी गई है तो उसकी सेवाएँ बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं। किसी भी रूप में पक्ष–प्रचार करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
6. प्रबंधन के पास शिक्षा, अनुभव, सीटीसी, वेतनमान आदि के समर्थन में कोई भी अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य मांगने का अधिकार सुरक्षित है।

महत्वपूर्ण तिथियां

1. **ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि: 12.02.2025 (प्रातः 10.00 बजे)**
2. **ऑनलाइन पंजीकरण बंद होने की तिथि: 14.03.2025 (सायं 6.00 बजे)**

विस्तृत विज्ञापन के लिए टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट www.thdc.co.in ⟶ quick links ⟶ career ⟶ New Job Opening को देखें।

विद्युत उत्पादन हमारी कटिबद्धता..... समाज का विकास हमारी प्रतिबद्धता

नवाचार से विश्वस्तरीय बनेगा लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, लागत पर लगेगी लगाम

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जीआईएस में जुट रहे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है। पॉलिसी के नवाचारों से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाकर आपूर्ति दक्षता को बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में दक्ष, विश्वसनीय और रणनीतिक रूप से स्थाई विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, जिससे वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम किया जा सके। इससे प्रदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए आकर्षक स्थल बन सकेगा।

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति राज्य को लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बनाने, निवेशकों को आकर्षित करने और व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। आगामी वर्षों में इससे मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार पोर्ट टर्न अराउंड समय को कम करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इससे राज्य की आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को सुधारा जा सकेगा। साथ ही पीसीएस-वन प्रणाली से ई-डिलीवरी आदेशों को पेश किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए डेडिकेटेड लैब बनाई जाएंगी, जिससे उत्पाद सुरक्षा नियमों और गुणवत्ता मानकों पर खरे उतर सकेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन डोर (आरएफआईडी) जैसे तकनीकी नवाचार सुरक्षा को बढ़ाएंगे और माल की आवाजाही भी तेज होगी। साथ ही यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म के समावेश से लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में डेटा का आदान-प्रदान सरल और तेज बनेगा। पॉलिसी के नवाचारों में ग्रीन कार्ड योजना भी शामिल है, जो ऐसे लॉजिस्टिक्स संचालकों को शीघ्र मंजूरी देगी, जो ग्रीन-ट्रांसपोर्टेशन को अपनाएंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से बढ़ेगी परिवहन दक्षता

अन्तर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के योग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य सरकार 20 से अधिक कार्गो टर्मिनल विकसित कर रही है। इससे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा। ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, जो माल ढुलाई को सुगम बनाएंगे। परिवहन लागत कम होने से व्यवसायियों का लाभ बढ़ेगा और प्रदेश में अधिक निवेश आकर्षित होगा।

निर्यात क्षमता बढ़ाने विकसित होगा विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 का एक महत्वपूर्ण अंग राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना भी है। इसके लिए पॉलिसी में निर्यात पार्क विकसित किए जाने के प्रावधान शामिल किये गए हैं। इन पार्कों के विकासक को स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी, साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अधिकतम 40 करोड़ रुपये अथवा प्रति एकड़ 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

लोधा समाज ने संस्कारों, परिश्रम और पराक्रम से प्रदेश के विकास में दिया महत्वपूर्ण योगदान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित लोधा समाज के कार्यक्रम को संबोधित किया

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोधा समाज के सामाजिक भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम की परंपरा से जुड़ने वाले लोधा समाज ने अपने संस्कारों, परिश्रम और पराक्रम से प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब-युवा-अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण अर्थात ज्ञान पर ध्यान के परिणाम स्वरूप सभी समाज, समर्थ और सक्षम हो रहे हैं और भारतीय संस्कृति एवं सनातन की ध्वजा सर्वत्र लहरा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर ही देश में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लोधा समाज द्वारा प्रदेश की राजधानी में बनाया जा रहा सामाजिक भवन, मांगलिक कार्यक्रमों की आयोजन स्थली बनने के साथ ही समाज के युवाओं को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण आदि प्राप्त करने के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामाजिक भवन के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा की तथा कहा कि राज्य सरकार सामाजिक गतिविधियों के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर है।

- **प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सभी समाज हो रहे हैं समर्थ और सक्षम।**
- **भवन के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों की जमीन संबंधी सभी कार्य घर बैठे हों, इस उद्देश्य से प्रदेश में साइबर तहसील की व्यवस्था आरंभ की गई है। किसानों को बड़े बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाने के लिए सोलर पंप सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश के सभी अंचलों में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना के साथ ही चंबल-कालीसिंध-पार्वती नदियों को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। किसानों के लाभ के लिए ही गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दूध पर बोनस देने की व्यवस्था भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्री समिट का क्रम आरंभ किया गया। 24-25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस वैश्विक आयोजन का शुभारंभ करेंगे। देश ही नहीं विदेश के औद्योगिक समूह भी प्रदेश में उपलब्ध पर्याप्त भूमि-जल-ऊर्जा की उपलब्धता के कारण मध्यप्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए उत्साहित हैं।

मुख्यमंत्री ने महालोक परिसर में किया नवनिर्मित सेतु का लोकार्पण

उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री महाकाल महालोक परिसर में रुद्रसागर पर नवनिर्मित सेतु का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि नामकरण इतिहास में सनातन संस्कृति और उज्जयिनी का परचम विश्व में लहराने वाले महान सम्राट अशोक के नाम पर 'सम्राट अशोक सेतु' किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री महाकाल के संरक्षण में होने से अवंतिका नगरी का कभी अंत नहीं हुआ। यहां तपस्या से सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। अनादिकाल से भारतवर्ष और सनातन संस्कृति के ध्वज-वाहकों राजा विक्रमादित्य, राजा भृतहरी, राजा अशोक आदि महान सम्राटों को संरक्षण दिया है।

खेलों में भी उपलब्धियां अर्जित कर रही है पुलिस

भोपाल, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और भोपाल में वॉटर स्पोर्ट्स का अर्धकुंभ आरंभ हो रहा है। पुलिस, नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। पुलिस बल के अनेक जवानों ने विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए देश का नाम रोशन किया है। राजा भोज द्वारा निर्मित भोपाल के ऐतिहासिक बड़े तालाब में अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन, प्रदेश सहित राजधानी भोपाल के लिए गौरव का विषय है। इस आयोजन से वॉटर स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहीं।

- **इस प्रतियोगिता में कयाकिंग, केनोइंग और रोइंग की प्रतियोगिताएं की गईं शामिला।**
- **प्रतियोगिता में कुल 27 प्रतिस्पर्धाओं में 360 पदक होंगे दांव पर।**
- **देश के राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 22 टीमों से 557 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, सेना इत्यादि में प्रवेश लेने वालों को जवान कहा जाता है, इस आशय से वे सेवाकाल तक जवान ही रहते हैं। वे उत्साह, उमंग और देश व देशवासियों के प्रति सेवा और समर्पण के भाव से कार्य करते रहें, यही कामना है। डॉ. यादव ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। खेल से मन, बुद्धि, आत्मा की शुचिता के संकल्प को भी साधा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की टीमों का राज्य सरकार की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हुए प्रतियोगिता में उनकी सफलता की कामना की।

डॉ. यादव ने कहा कि पौराणिक मान्यता के अनुसार पंचमहाभूतों में जल की विशेष महत्ता है। जीव की उत्पत्ति जल से होती है, अत: जीव सदैव जल की ओर विशेष रूप से आकर्षित होते हैं।

ग्लोबल एक्सपो-2025 में सांस्कृतिक धरोहर को मिला वैश्विक मंच

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत टैक्स ग्लोबल एक्सपो-2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे भारत की पारंपरिक परिधान परम्परा और आधुनिक टेक्सटाइल का संगम कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक्सपो भारत की समृद्ध परिधान परम्परा को वैश्विक मंच प्रदान करेगा।

भारत मण्डपम में आयोजित इस भव्य आयोजन में 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और निवेशकों ने भाग लिया। मध्यप्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2025 में पार्टनर स्टेट के रूप में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, जो प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच प्रदान करेगी। मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ने राज्य के वस्त्र, गारमेंट और अपैरेल उद्योग की समृद्धि और विकास को प्रदर्शित करने के लिये भव्य मध्यप्रदेश स्टेट पेवेलियन स्थापित किया। पेवेलियन में राज्य की विशेष नीतियों और उद्योग के विकास में मिली सफलता को प्रमुखता से दर्शाया गया। पेवेलियन में प्रमुख आकर्षण के रूप में मध्यप्रदेश द्वारा स्थापित किया गया पीएम मित्रा पार्क, जो धार जिले में स्थित है, को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। इस पार्क के माध्यम से राज्य में वस्त्र उद्योग को लेकर सरकार द्वारा किये गये निवेश और प्रोत्साहनों को उजागर किया गया।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

जीआईएस में ओडीओपी एक्स-पो से उत्पादकों को मिलेगा ग्लोबल मंच

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'एक जिला-एक उत्पाद' हमारे कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक्स-पो के माध्यम से हम अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच देने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के उद्योगों, विशेष रूप से हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यह एक्स-पो न केवल हमारे कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करेगा, बल्कि उन्हें नए व्यावसायिक अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) एक्स-पो प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इसमें मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे स्थानीय शिल्प, कृषि और खाद्य उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

ओडीओपी जोन : परंपरा और नवाचार का संगम

एक्स-पो में प्रदेश के 38 ओडीओपी उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे, जिन्हें लाइव काउंटर और प्रोसेस काउंटर में विभाजित किया गया है। लाइव काउंटर में बाग प्रिंट, जरी जरदोजी, बाटिक प्रिंट, कालीन, चंदेरी साड़ी, बांस, बलुआ पत्थर और कपड़े की जैकेट जैसे आठ प्रमुख उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया को कारीगरों द्वारा लाइव प्रस्तुत किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रतिनिधि और अतिथि कारीगरों के मार्गदर्शन में खुद भी इन उत्पादों को बनाने का अनुभव ले सकेंगे।

खाद्य और कृषि उत्पादों की झलक

एक्स-पो में खाद्य, मसाले और फलों से जुड़े 32 ओडीओपी उत्पादों के स्टॉल पर उनकी निर्माण प्रक्रिया के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। यहां प्रतिनिधि इन उत्पादों को न केवल देख और समझ सकेंगे, बल्कि उन्हें खरीद भी पाएंगे। साथ ही 16 लाइव काउंटरों पर मध्यप्रदेश की पारंपरिक कला और शिल्प का प्रदर्शन होगा।

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ओडीओपी एक्स-पो न केवल मध्यप्रदेश के शिल्प और उत्पादों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा, बल्कि कारीगरों और निवेशकों के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका भी निभाएगा।

बेसहारा एवं निराश्रित गौ-वंशों की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर के ग्राम उमरिया में अत्याधुनिक गौशाला में पहुंचकर गौ-पूजन किया

जबलपुर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर के ग्राम उमरिया में 53 एकड़ में बनाई जा रही गौशाला परियोजना के पहले चरण का भूमिपूजन कर संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों की नगरी जबालीपुरम धन्य हुई है। यह आनंद का धाम बना है। जिले में अत्याधुनिक गौ-शाला बनाये जाने की नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि गौ-संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की नीति अनुसार कहीं भी गौ-माता को लावारिस-निराश्रित नहीं रहने दिया जायेगा। प्रदेश के बड़े महानगरों की तरह अन्य बड़ी नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में गौ-शालाओं का निर्माण कर इनकी क्षमताओं को 10 हजार तक पहुंचाने का कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2600 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेहूं लेने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को 2 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि इसी माह से दी जायेगी।

- **किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा गेहूं।**
- **धान उत्पादक किसानों को 2 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।**
- **10 हजार गौवंशों को मिलेगा आश्रय।**
- **187.43 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया शिलान्यास व लोकार्पण।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय स्तर पर गौ-शालाएं खुलेंगी, जिनमें अधिक आयु की निराश्रित और अशक्त गौ-वंशों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौ-शालाओं के प्रत्येक गौ-वंश के लिए 40 रुपये प्रतिदिन दिये जा रहे हैं। साथ ही साथ घर-घर तक गौ-पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 10 से अधिक गौ-वंश पालने वाले व्यक्ति को शासन की ओर से अनुदान दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की आजादी के साथ ही अन्य देश भी आजाद हुए। उन्होंने अपनी संस्कृति से जुड़ाव बनाये रखा। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इजराइल की देशभक्ति का उदाहरण भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गरीब, युवा, महिला एवं किसान कल्याण एवं विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

जीआईएस में औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर होगा मंथन

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता, निवेशक और विशेषज्ञ मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर मंथन करने के लिए एक मंच पर जुटेंगे। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, नवकरणीय ऊर्जा, हेल्थ केयर, खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्ट-अप्स, वित्तीय सेवाओं और पर्यटन आदि क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं हैं। समिट में मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और संभावनाओं और अवसरों का लाभ उठाने के लिये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के दिग्गज उद्योगपति अपने अनुभव, विचार और रणनीतियां साझा करेंगे।

टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग

मध्यप्रदेश टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण कई बड़ी कंपनियां मध्यप्रदेश में निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं। समिट में टीडब्ल्यूई ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री इंगो सोलर, एईपीसी के महासचिव श्री मिथिलेश्वर ठाकुर, आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के चेयरमैन श्री रिजू झुनझुनवाला, सेखानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक श्री रोनिश सेखानी और प्रतिभा सिंटेक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री श्रेयस्कर चौधरी टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश और विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर

मध्यप्रदेश फार्मा और हेल्थ केयर क्षेत्र में सहजना एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज के उपाध्यक्ष श्री राजीव छिब्बर, इन्वॉल्यूशन हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक श्री गौरव अग्रवाल, बायो-मेरियू इंडिया के प्रमुख श्री बिवाश चक्रवर्ती, सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्लोबल हेड ऑपरेशंस श्री राहुल अवस्थी और आईपीसीए लेबोरेट्रीज के प्रबंध निदेशक श्री अजीत कुमार जैन विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

नवकरणीय ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी

ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बन रहा है। टाटा पॉवर के श्री दीपेश नंदा, ओ-2 पॉवर के श्री पराग शर्मा, अवाडा एनर्जी के श्री विनीत मित्तल, रिन्यू पॉवर के श्री सुमंत सिन्हा, जिंदल के श्री अमित मित्तल, वारी एनर्जी के श्री पंकज दोशी, ग्रीनको के श्री अनिल कुमार जैसे प्रमुख निवेशक राज्य में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसरों पर चर्चा करेंगे।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में आईटीसी एग्री बिजनेस डिवीजन के श्री गणेश के. सुंदररमन, पेप्सिको इंडिया के श्री अनुकूल जोश, ग्रीन ग्रेन के श्री प्रतीक शर्मा और आईएफसी वर्ल्ड बैंक के श्री विजयसैकर कलवकोंडा निवेश और विकास की संभावनाओं पर विचार करेंगे।

स्टार्ट-अप्स और नवाचार

स्टार्ट-अप्स और इनोवेशन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनोगुरु के संस्थापक एवं सीईओ श्री वैदंत जैन युवा उद्यमी और निवेशक इस क्षेत्र में नए अवसरों पर मंथन करेंगे।

खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देकर करेंगे तैयार

जबलपुर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेल अकादमी की सौगात दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे सभी सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों को भी दी जाएंगी। खेल मंत्रालय द्वारा जो भी खेल नीति तय की जायेगी, उसे राज्य में अमल में लाया जायेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ओलंपिक, एशियाड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए भारत ने खेलों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर के रांझी में 26.80 करोड़ की लागत से बनी राज्य तीरंदाजी खेल अकादमी का लोकार्पण कर समारोह को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि जबलपुर में आज लोकार्पित हुई राज्य स्तरीय खेल अकादमी स्व. ईश्वरदास रोहाणी के नाम से जानी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश नए दौर में प्रवेश कर रहा है। इस नए दौर में हम हर क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्यों की गति बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिये कि उपनगरीय क्षेत्र रांझी के शारदा नगर, शांति नगर, राम नगर और उदय नगर के पात्र व्यक्तियों का परीक्षण कर आवासीय पट्टे प्रदान किये जायें।

जीवन में प्रगति के लिये शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण - राज्यपाल

ग्वालियर, जीवन में प्रगति के लिये शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति या समाज प्रगति नहीं कर सकता। सहरिया समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण है, बेटे के साथ-साथ बेटी को भी शिक्षित करें, तभी हम प्रगति की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। ये बातें राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने ग्वालियर की ग्राम पंचायत चैत में सहरिया समुदाय से संवाद करते हुए कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहरिया, भारिया एवं बैगा समुदाय के सम्पूर्ण विकास के लिये केन्द्र सरकार की ओर से 24 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। इसके माध्यम से इन समुदाय के लोगों को आवास, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। पीएम जनमन योजना के तहत 11 मूलभूत सुविधाओं को 9 विभागों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को मिले, इसके सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं समाज के उत्थान के लिये संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर सहरिया परिवारों को अपने जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि सहरिया परिवार में रानी दुर्गावती, रानी कमलावती और बिरसा मुण्डा जैसे महान लोग हुए हैं, जिन्होंने समाज और देश के लिये अनेक कार्य किए हैं। हम सबको इनसे प्रेरणा लेकर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिये कार्य करना चाहिए।

श्री पटेल ने ग्राम पंचायत चैत में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत निर्मित आवास का भी अवलोकन किया।

प्रदेश में गिद्धों की गणना हुई शुरू

भोपाल, प्रदेश में गिद्धों की संख्या और उनकी स्थिति का आकलन करने के लिये गिद्ध गणना वर्ष 2024-25 पूरे प्रदेश में 17 फरवरी से प्रारंभ होगी जो दो चरणों में की जायेगी। गिद्धों के आकलन की गणना वर्ष में दो बार की जाती है। शीतकालीन गिद्ध गणना 17, 18 एवं 19 फरवरी को होगी और ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना 29 अप्रैल 2025 को की जायेगी। शीतकालीन गिद्ध गणना सुबह 7 बजे से 8 बजे तक होगी। ऐसे स्थान जहां पर ऊंची चट्टान हैं, उन स्थानों पर अधिकतम 9 बजे तक गणना की जा सकती है।

किसानों को प्रति हेक्टेयर दो हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

उमरिया, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उमरिया जिले के नौरोजाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से उनके बैंक खाते में अंतरित करेगी। इसका लाभ छोटे किसानों को भी मिलेगा। किसानों के हित में प्रदेश सरकार ने पहले कोदो-कुटकी के उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया। गेहूं उत्पादक किसानों से भी 2600 रुपये प्रति क्विंटल उपज खरीदी जाएगी। दुग्ध उत्पादक किसानों से सरकार दूध खरीदेगी और उन्हें बोनस भी देगी। किसानों को सोलर पंप देकर उन्हें बिजली के बिल से भी मुक्ति दिलाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। उमरिया में सोन नदी पर 45 करोड़ रुपये की लागत से नए पुल का निर्माण होगा। एक अन्य पुल भी 32 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा।

- **यह वर्ष अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।**
- **250 तक की आबादी वाले गांवों में भी होगा सड़कों का निर्माण।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व काफी विराट था। इस वर्ष उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। देश में पहली बार गांव-गरीब के बारे में किसी ने सोचा तो वे श्रद्धेय वाजपेयी जी थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आज गांवों में आवागमन सुगम हुआ है। गांवों को विकास और शहरों से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति भारत रत्न अटलजी ही थे, जिनके सामने संसद में पक्ष-विपक्ष के सभी नेता नतमस्तक रहते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संकल्प लिया है कि अब 250 की आबादी वाले गांवों में भी सड़कें बनाई जाएंगी। गरीबों को पक्का मकान देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में आनंद होना चाहिए। यह प्रदेश सरकार का संकल्प है। गरीबों का भी देश-प्रदेश में अधिकार है।

समाज के वंचित वर्ग को पक्के मकान मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की हैं।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के निर्णय

प्रदेश और निवेशकों के हित में मंत्रिपरिषद ने अनेक नीतियों को दी मंजूरी

- प्रदेश को जैव ईंधन उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए बायोफ्यूल योजना-2025 का किया अनुमोदन।
- मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी-2025 का भी हुआ अनुमोदन।
- मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2025 का किया अनुमोदन।
- मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2025 को मिला अनुमोदन।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित किया

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा शहरी क्षेत्र में रियल स्टेट से संबंधित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 'एकीकृत टाउनशिप नीति 2025' लागू किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी। एकीकृत टाउनशिप नीति लैंड पूलिंग के माध्यम से भूमि का विकास करने के उद्देश्य से बनायी गयी है। नीति के लागू होने से जहां एक ओर वृहद स्वरूप की टाउनशिप विकसित होगी, वहीं दूसरी ओर प्रचलित प्रक्रिया अनुसार भी कॉलोनियों का विकास यथावत होता रहेगा।

एमएसएमई विकास नीति-2025

मंत्रिपरिषद द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के संवर्धन के लिए नवीन मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2025 का अनुमोदन दिया गया। निर्णय अनुसार औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक नीति-2025 और एक्सपोर्ट पॉलिसी-2025 का लाभ एमएसएमई को प्रदान किया जायेगा।

नई नीति में मध्यम इकाई को 100 से अधिक रोज़गार देने पर डेढ़ गुना अनुदान, रोज़गार सृजन सेक्टर में प्रति कर्मचारी 5 हजार रुपये प्रति माह 5 वर्ष के लिए एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 13 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी। नवीन क्षेत्र जैसे एमएसएमई एक्सचेंज, लीन इंजीनियरिंग, टेस्टिंग लैब और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सहायता दी जायेगी।

मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2025

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2025 का अनुमोदन किया गया। नीति अन्तर्गत स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधा, सहायता एवं फेसिलिटेशन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में उपयुक्त स्थान पर एक मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर का विकास एवं संचालन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अग्रणी संस्थाओं के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी अंतर्गत स्थापित कर इसके सेटेलाइट सेंटर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी स्थापित किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्टार्ट-अप्स को बैंकों के माध्यम से कोलेट्रल-फ्री ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें केन्द्र सरकार की स्टार्ट-अप्स के लिये ऋण गारंटी स्कीम अंतर्गत कवरेज तथा प्रचलित दर पर देय गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 05 वर्षों तक) एवं वितरित ऋण पर 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान प्रतिपूर्ति (अधिकतम 05 वर्षों तक) की जायेगी। नीति अंतर्गत 10 हजार स्टार्ट-अप की स्थापना की जाना है।

सिविल एविएशन पॉलिसी-2025

मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश में नये वायु मार्गों का विकास करने और देश के अन्य हिस्सों तथा दुनिया के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों को जोड़कर पर्यटन तथा धार्मिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की उड़ान (राष्ट्रीय नागर विमानन प्रोत्साहन नीति) योजना के समन्वय से मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी-2025 का अनुमोदन दिया गया है।

विमानन नीति के माध्यम से भविष्य में 3 एमआरओ हब विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही 75 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई पट्टी और 150 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा एवं प्रत्येक तहसील स्तर पर 45 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक पक्का हेलीपेड विकसित किया जायेगा। राज्य के पर्यटन तथा धार्मिक महत्व के स्थलों को वर्ष 2030 तक किफायती दामों में हवाई सम्पर्क से जोड़ा जायेगा।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025

मंत्रिपरिषद द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन को आमजन के लिए भविष्य का मुख्य परिवहन का साधन बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 की स्वीकृति दी गई है। नीति अंतर्गत 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बसों इत्यादि के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।

मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2025 अंतर्गत प्रदेश को जैव ईंधन उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए बाँयो फ्यूल योजना-2025 का अनुमोदन किया गया।

लेक व्यू रेसीडेंसी होटल, भोपाल को विकास, संचालन एवं रखरखाव और प्रबंधन के लिए पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप में 60 वर्षों की लीज पर दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। लीज अवधि को आपसी सहमती से समान शर्तों पर आगामी 10 वर्षों हेतु एक बार बढ़ाया जा सकेगा। निर्णय अनुसार होटल लेक व्यू रेसीडेंसी भोपाल की मध्यप्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में कलेक्टर भोपाल द्वारा निष्पादित श्यामला हिल्स स्थित खसरा क्रमांक 21/3 में से 7.16 एकड़ की लीज अवधि में वर्ष 2042 से 60 वर्ष अर्थात वर्ष 2102 तक एकमुश्त वृद्धि किए जाने एवं उक्त लीज को निजी निवेशक के पक्ष में एमपीएसटीडीसी तथा एमपीएचसीएल द्वारा सबलीज (उपपट्टा) दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

फैक्ट फाइल

मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025

मध्यप्रदेश ड्रोन निर्माण और प्रौद्योगिकी का हब बनने को तैयार

वर्तमान युग में ड्रोन के उपयोग से विकास के कई क्षेत्रों में अनंत संभावनाएं विकसित हुई हैं। देश में डिजिटलीकरण के साथ सरकारी नीतियों, प्रौद्योगिकी के विकास और वित्तीय सहयोग के चलते ड्रोन क्षेत्र लोकप्रिय हो रहा है। इसका निगरानी, सुरक्षा और संरक्षण, वाणिज्यिक उद्योग, लॉजिस्टिक और परिवहन, कृषि तथा खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण उपयोग है। ड्रोन दीदी योजना के प्रभावी परिणाम प्राप्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल से प्रेरित होकर प्रदेश में नीतिगत निर्णय लिये गये। ड्रोन के उपयोग और परिणाम को देखते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025 को स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रदेश को ड्रोन निर्माण और प्रौद्योगिकी का प्रमुख हब बनाने के लिए संपूर्ण कार्य योजना बनाई गई है।

इस नीति में ड्रोन के सुरक्षित और कुशलतम उपयोग के माध्यम से नवाचार, आर्थिक समृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने वाले विषयों एवं तथ्यों को शामिल किया गया है। ड्रोन नीति सरकार के ड्रोन डेटा और इमेजरी के लिए एक केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म होगा।

क्या लाभ होगा नीति से

प्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी बनेगी। ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी से विभिन्न विभागों के मध्य परस्पर डेटा साझा करने के लिए सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति जीआईएस आधारित योजना और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके बेहतर निगरानी तंत्र विकसित करेगी। यह रिपॉजिटरी तत्काल अद्यतन निगरानी सुविधा प्रदान करेगी, जिससे संसाधनों का त्रुटिरहित आवंटन होगा और अधोसंरचनात्मक विकास में सहयोग मिलेगा। इससे बेहतर समन्वय, निर्णय-प्रक्रिया में मदद मिलने के साथ लागत-समय का सदुपयोग होगा और परियोजनाओं की समीक्षा में सुधार भी होगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि डेटा प्रबंधन सुरक्षित रूप से किया जाए और सहयोगी भागीदारों के साथ रिपॉजिटरी की प्रबंधन व्यवस्था पुख्ता रखी जाए। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य की एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए सभी ड्रोन डेटा को राष्ट्रीय भौगोलिक नीति-2022 या उसके बाद के किसी संशोधन या नीति के अनुसार डेटा सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अंतर्गत संग्रहित किया जाए।

कृषि क्षेत्र में उपयोग

ड्रोन से फसल की सेहत की निगरानी, रोगों का पता लगाने और फसल की पैदावार का मूल्यांकन करने में सहायता मिल रही है। ड्रोन उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव सटीकता से कर सकते हैं, जिससे अपशिष्ट और नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा।

आपदा प्रबंधन में उपयोग

ड्रोन, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में थर्मल इमेजिंग और हाई-रिजोल्यूशन कैमरों का उपयोग कर प्रभावित लोगों का पता लगा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत तस्वीरें देख बचाव के प्रयासों में मदद कर रहे हैं।

निरीक्षण में उपयोग

ड्रोन पुलों, भवनों और अन्य बुनियादी ढांचे का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें रखरखाव और सुरक्षा मूल्यांकन शामिल हैं। जंगलों की सेहत की निगरानी, अवैध लकड़ी कटाई का पता लगाने और जंगल की आग के प्रभाव का मूल्यांकन भी ड्रोन से किया जा रहा है।

नीति के प्रमुख स्तंभ

ड्रोन इको सिस्टम, कौशल विकास, सेक्टर प्रमोशन और वित्तीय प्रोत्साहन ड्रोन नीति के प्रमुख स्तंभ हैं। इनसे तकनीकी संस्थानों में ड्रोन संबंधी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। ड्रोन इको सिस्टम एआई और नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्तीय प्रोत्साहन

वाणिज्यिक उद्योग और संरक्षण तथा उपयोग और खाद्य उत्पादन में ड्रोन नीति की घोषणा के बाद डीएसडीएम, डीईएस इकाइयों द्वारा किए गए नए निवेश के लिये 40 प्रतिशत पूंजी निवेश (अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक) की सब्सिडी और लीज रेंटल पर 3 वर्ष तक 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति या प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक, जो भी कम हो मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा पहचाने गये क्षेत्रों में आर एंड डी परियोजना शुरू करने के लिये 2 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलेगा।

- शशांक मणि पांडे

(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

ड्रोन क्या है

यह बिना पायलट वाला यंत्र है जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यह कई प्रकार से अभिनव समाधान प्रस्तुत करता है और मानव श्रम की बचत करता है। इस तकनीकी से समय पर डेटा संधारित हो जाता है। सटीक और दक्षता के साथ कठिन स्थानों से डेटा संग्रह हो जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से कई क्षेत्रों के लिए यह अमूल्य उपकरण साबित हो रहा है।

मुख्य बिंदु

- मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 स्वीकृत।
- भविष्य में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ेगा।
- मध्यप्रदेश की ड्रोन प्रौद्योगिकी में अग्रणी राज्य बनने की संभावना तय।
- ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति पर कार्य प्रारंभ।
- ड्रोन टेक्नोलॉजी को उपयोगी बनाने के लिए शीघ्र बनेगी ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी।
- नीति से आगामी पांच वर्षों में 370 करोड़ रुपये का निवेश संभव है।
- इससे लगभग 50 हजार रोजगार होंगे सृजित।

चर्चा

फोर्ट विलियम

अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा

कोलकाता स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया है। इसे नया नाम विजय दुर्ग दिया गया है। इसका नाम महाराष्ट्र के प्राचीनतम सिंधुदुर्ग किले के नाम पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा नौसैनिक अड्डा था। इसके अतिरिक्त किले के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस और सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट किया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इस दुर्ग का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था।

अभ्यास साइक्लोन

भारत और मिस्र के बीच संपन्न

भारत और मिस्र के बीच तीसरा संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। यह अभ्यास 10 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। अभ्यास साइक्लोन एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो भारत और मिस्र में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2024 में मिस्र में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर-संचालन, संयुक्तता और विशेष संचालन रणनीति के आपसी आदान-प्रदान को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना है।

नीति आयोग ने

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पर पॉलिसी रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग ने 'राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के जरिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार' शीर्षक से एक पॉलिसी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी, नीति आयोग में सदस्य (शिक्षा) डॉ. विनोद कुमार पॉल, नीति आयोग के सीईओ श्री. बीवीआर सुब्रमण्यम, उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) महासचिव डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल द्वारा जारी की गई। यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला नीति दस्तावेज है, जो खासकर राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (एसपीयू) पर केंद्रित है।

चमन अरोड़ा

साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित

दिवंगत चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक 'इक होर अश्वत्थामा' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 (डोगरी) के लिए चुना गया है। यह पुस्तक लघु कहानियों का संग्रह है, जिसे तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया। पुस्तक का चयन इस उद्देश्य के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार जूरी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वर्गीय चमन अरोड़ा के परिवार के सदस्य या नामित व्यक्ति को 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में दिया जाएगा।

भारत में

दूसरी बार एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम आयोजित

14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम (एएफएएफ) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय "एशिया-प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना" था। इसका आयोजन एशियाई मत्स्य पालन सोसायटी (एएफएस), कुआलालंपुर; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली; मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ), भारत सरकार; और एशियाई मत्स्य पालन सोसायटी भारतीय शाखा (एएफएसआईबी), बैंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 2007 में कोच्चि में आयोजित 8वें एएफएएफ के बाद यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम दूसरी बार भारत में आयोजित किया गया।

एचएस कोड

चावल के निर्यात के लिए पहली बार जारी

भारत सरकार ने भौगोलिक संकेत (GI) टैग वाले चावल के निर्यात के लिए एचएस (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन किया है। यह पहली बार है कि जीआई मान्यता प्राप्त चावल के लिए एचएस कोड पेश किया गया है। विश्व सीमा शुल्क संगठन एचएस कोड को प्रबंधित करता है, जिसे प्रत्येक पांच वर्ष में संशोधित किया जाता है। इसका उपयोग वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिये एक वैश्विक मानक के रूप में किया जाता है। यह पहचान, शुल्क और व्यापार सांख्यिकी में मदद करता है।

"Get World-class Training & Be Future Ready..."

Sant Shiromani Ravidas

Global Skills Park

(An Excellent Institution under the Government of Madhya Pradesh)

Key Highlights

- Training fee at extremely concessional rates
- State-of-the-art training infrastructure
- Internationally bench marked advanced curriculum, course design, and equipments as per ITEES Singapore standards
- National and international placement assistance
- Life skills training and on-the-job training
- Scholarship facilities
- Hostel facilities
- One student, one machine ratio

98% Placement

One-Year Courses for the 2025 Session

- Advanced Electrical Technology (Power and Control) (80 Seats)
- Advanced Electronics (Mobile Device and IoT Integration) (80 Seats)
- Advanced Networking and Systems Administration (80 Seats)
- Advanced Air Conditioning and Refrigeration (80 Seats)
- Advanced Precision Engineering (120 Seats) May, 2025
- Advanced Automotive Technology (40 Seats)
- Advanced Mechanical Technology (40 Seats)
- Advanced Mechatronics (40 Seats)
- Advanced Mechanical and Electrical Services (80 Seats)

For more detail scan QR

Seats Distribution

- 5% Seats for International Students
- 20% Seats for Students from Other States
- 75% Seats for Students from Madhya Pradesh

Eligibility : ITI/Degree/Diploma in the relevant field

Admission Process : Based on merit

Reservation : As per Madhya Pradesh Government norms for SC/ST/OBC/35% reservation for Women

Important Dates : Admission Start Date : January 17, 2025
Admission End Date : March 15, 2025

Contact Information : Sant Shiromani Ravidas Global Skills Park
Hazrat Nizamuddin Colony Road, Narela Shankari, Bhopal (M.P.), admission.gsp@mp.gov.in
Contact No. 0755-2706205, 9981919733 | 9713992665 | 9893346258

Interested applicants may apply at : https://admissions.globalskillspark.in
Department of Technical Education, Skill Development and Employment, Government of Madhya Pradesh
D-11181/R-50600/2025

SHRI REWA GURJAR BAL NIKETAN COLLEGE, SANAWAD

(Approved by Govt. of MP and Affiliated to KTB University, Khargone, DAVV, Indore)
Khargone Road, Sanawad-451111
Ph.No. 8839615055, E-mail : srg.college@gmail.com
Advertisement for Principal and Various Regular Faculty in the College (under code 28 Norms)

Subjects :
Botany/Microbiology/Biotechnology/Bioinformatics/Commerce/Management (For BBA & MBA)/Sociology/Mathematics/Political Science/Seeds Technology/Computer/Hindi/English Literature/Chemistry/Zoology/Physics/Horticulture/Sports/Librarian

Posts :
Principal/Professor/Associate Professor/Assistant Professor/Lecturer/Lab Technician.

For other Course : B.Ed. 16 Posts

*Candidate who are eligible NET/SET/Ph.D. under Code-28 as per UGC Norms of University can apply within **15 days.**

R-50608/2025 **PRESIDENT**

श्री हरिरायजी शिक्षण समिति धार द्वारा संचालित

एल.एस.ए. कॉलेज धार, जिला-धार (म.प्र.)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से संबद्धता प्राप्त

आवश्यकता है

विश्वविद्यालय परिनियम-28 के अंतर्गत

क्र.	बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु	आवश्यकता
1.	प्राचार्य	01
	सहायक प्राध्यापक	
1.	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में	04
2.	शिक्षाशास्त्र विषय (गणित/विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/भाषा)	08
3.	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	01
4.	ललित कला	01
5.	प्रदर्शन कला (संगीत/नृत्य/थिएटर)	01

योग्यता :– एन.सी.टी.ई./मध्यप्रदेश शासन के मापदण्डों के अनुसार, वेतन एन.सी.टी.ई./यूजीसी के मापदण्डों के अनुसार

विज्ञापन दिनांक से 07 दिवस में आवेदन करें।
महाविद्यालय का पता - एल.एस.ए. कॉलेज धार
214/2, जेतपुरा धार, जिला धार (म.प्र.) पिन कोड-454001
मो.नं. - 7389221000, ईमेल आईडी - Isadhar@aol.com

R-50607/2025

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर

क्रमांक. 1431/स्था/अराज/2025/ **जबलपुर, दिनांक : 18.02.2025**

सूचना

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा ने.सु.च.बो. मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के स्टॉफ नर्स (नर्सिंग ऑफिसर) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जारी चयन सूची दिनांक 27 जनवरी 2022 के तहत एवं उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 2211/2023 शहनाज खातून एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 13.04.2024 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल का आदेश क्रमांक 1618 एफ 6/5/0001/2024/मेडि-सत्रह (2) भोपाल दिनांक 05.12.2024 के तहत प्राप्त स्वीकृति के परिपालन में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची में मेरिट के आधार पर संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 06.01.2025 से 07.01.2025 तथा 27.01.2025 से 28.01.2025 को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था, उक्त दिनांक को जो अभ्यार्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो पाये हैं उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए **दिनांक 28.02.2025 शुक्रवार, प्रातः 10:30 बजे** दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित समयावधि में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यार्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त समझी जावेगी एवं किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जावेगा।

नोट :- 1. भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी हेतु चिकित्सा महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट **www.nscbmc.ac.in** पर विजिट करें।

अधिष्ठाता

जी-23348/50620/2025 **नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर**

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. LIMITED

(A Government of M.P. Undertaking)
Regional Office, Bhopal (M.P.), Tawa Complex, Bittan Market
E-5, Arera Colony, Bhopal, Phone : (0) +917552420301-2-3

Date : 17.02.2025

NOTICE INVITING TENDER FOR YEAR - 2024-25

Online Tender for the following works are invited on the E-procurement System portal mptenders.gov.in:- as detailed below :-

NIT No.	Subject	Probable amount of Contract (In Lakhs)
61	Miscellaneous Civil/Electrical/Water supply and Road work at Various Industrial Area of MPIDC RO Bhopal (M.P.)	400.00

Detailed NIT along with other details can be downloaded/viewed on above mentioned portal from 18.02.2025 10:30 Hrs.

M.P. Madhayam/118841/2025 R-50617/2025 **EXECUTIVE ENGINEER**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
3rd Floor, Vikas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 332/MTN/2025

No./2255/22/D-12/NIT-Maint./2025 **Bhopal, Dated : 17.02.2025**

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below :-

- **SSR Applicable :-** SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority effective from 01.01.2024 and amendments upto issue date of NIT.
- **Table No. 1 :- Name of Work -** Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 5 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Agar Malwa	2	3729435.00
2.	Ashoknagar	2	7491402.00
3.	Betul	2	68892062.00
4.	Bhind	1	758011.00
5.	Chhatarpur	1	6189817.00
6.	Chhindwara	1	9588547.00
7.	Damoh	3	115852495.00
8.	Dewas	7	90171298.00
9.	Guna	2	20858031.00
10.	Harda	1	21008334.00
11.	Mandsaur	3	23468457.00
12.	Narmadapuram	2	29113757.00
13.	Panna	2	3043202.00
14.	Raisen	9	98695255.00
15.	Rajgarh	3	93349950.00
16.	Ratlam	3	118653342.00
17.	Rewa	3	6373100.00
18.	Satna	2	25861068.00
19.	Sehore	2	15983592.00
20.	Seoni	5	50369256.00
21.	Shahdol	2	27857651.00
22.	Shajapur	1	17224474.00
23.	Shivpuri	4	134780718.00
24.	Singrauli	1	11029406.00
25.	Ujjain	2	18977143.00
26.	Umaria	1	1584253.00
27.	Vidisha	2	3657851.00

- **Table No. 2 :- Name of Work-** Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 10 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Balaghat	1	13620580.00
2.	Betul	2	27780404.00
3.	Chhatarpur	1	9339423.00
4.	Chhindwara	2	8123609.00
5.	Damoh	2	17308083.00
6.	Datia	1	19030212.00
7.	Dewas	1	14919268.00
8.	Guna	2	21034268.00
9.	Gwalior	1	11086854.00
10.	Harda	1	9066262.00
11.	Mandla	1	15299400.00
12.	Mandsaur	3	27530176.00
13.	Narsinghpur	1	7311034.00
14.	Neemuch	1	5100179.00
15.	Ratlam	2	36138565.00
16.	Rewa	1	3899817.00
17.	Sagar	4	53945742.00
18.	Satna	2	26592294.00
19.	Sehore	2	5781072.00
20.	Seoni	1	6946172.00
21.	Shajapur	3	35608749.00
22.	Sheopur	1	7238837.00
23.	Shivpuri	4	48134957.00
24.	Sidhi	1	15909114.00
25.	Singrauli	3	21853072.00
26.	Ujjain	1	14034613.00

- **Table No. 3 :- Name of Work -** Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 15 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Ashoknagar	1	12348882.00
2.	Bhind	1	11122635.00
3.	Chhatarpur	2	69956597.00
4.	Chhindwara	2	24081759.00
5.	Damoh	3	57016001.00
6.	Guna	3	27286145.00
7.	Panna	3	59860443.00
8.	Raisen	1	31204886.00
9.	Rajgarh	2	34690772.00
10.	Ratlam	1	6496378.00
11.	Rewa	1	5241190.00
12.	Satna	5	71084015.00
13.	Sehore	3	43607573.00
14.	Seoni	9	103910668.00
15.	Shivpuri	2	12629293.00
16.	Sidhi	2	12877267.00
17.	Tikamgarh	1	17067206.00
18.	Singrauli	1	4566182.00
19.	Ujjain	2	19169429.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **21.02.2025 from 17:30 hrs.** and last date for online bid submission is **18.03.2025 (17:00 hrs.)**.
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/118836/2025 R-50616/2025 **(TENDER)**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
3rd Floor, Vikas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)
No./2258/22/D-12/MPRRDA/2025 Bhopal, Dated : 17.02.2025

NOTICE INVITING TENDER No. 1216 (PMGSY-PART)

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **www.pmgsytenders.gov.in** as detailed below :-

- **Name of Work** – Construction/Up-gradation of Rural Roads under PMGSY including maintenance for Five year after construction.

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Burhanpur	1	26664000/-

1. Bid document may be purchased online from **19.02.2025 (17:30 hrs.)** and last date for online bid submission is **13.03.2025 (17:00 hrs.)**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/118835/2025 R-50615/2025 **(TENDER)**

धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में दतिया जिले के ग्राम हसापुर का चयन

दतिया, जिले की ग्राम पंचायत भरोली के ग्राम हसापुर का पीएम जनमन बाल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में चयन किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति आबादी के लिये समान अवसरों का सृजन, सामाजिक, आर्थिक स्तर का विकास, बुनियादी ढाँचे के सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में प्रगति करना है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में दतिया कलेक्टर श्री संदीप कुमार माकिन पीएम जनमन बाल स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए।

'मेरी सड़क' ऐप डाउनलोड कर, फीडबेक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
3rd Floor, Vikas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

No./2261/22/D-12/MPRRDA/2025 Bhopal, Dated : 17.02.2025

NOTICE INVITING TENDER No. 1215 (PM-JANMAN)

(Batch-I, II, III & IV, Year-2024-25)

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.pmgsytenders.gov.in** as detailed below:-

- **Name of Work** – Construction/Up-gradation of Rural Roads under PMGSY including maintenance for Five year after construction.
- **SSR Applicable :-** SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority, effective from 01.01.2024 and amended upto issue date of NIT.
- **Table-1, PMAJANMAN-Batch-I**

S. No.	Name of District	No. of Packages	No. of Road	Total Length (in kms.)	Total PAC (In Rs.)
1.	Shahdol	1	1	0.64	3349068/-

- **Table-2, PMAJANMAN-Batch-II**

S. No.	Name of District	No. of Packages	No. of Road	Total Length (in kms.)	Total PAC (In Rs.)
1.	Vidisha	1	1	0.59	4306000/-

- **Table-3, PMAJANMAN-Batch-III**

S. No.	Name of District	No. of Packages	No. of Road	Total Length (in kms.)	Total PAC (In Rs.)
1.	Shivpuri	1	1	4.75	38402000/-
2.	Sidhi	1	3	10.45	71504000/-
3.	Singrauli	2	2	5.00	32664549/-

- **Table-4, PMAJANMAN-Batch-IV**

S. No.	Name of District	No. of Packages	No. of Road	Total Length (in kms.)	Total PAC (In Rs.)
1.	Chhindwara	1	2	5.10	35093000/-
2.	Singrauli	2	2	3.51	21181227/-

1. **Availability of Bid Documents and mode of submission:** The bid document is available online and should be submitted online in **www.pmgsytenders.gov.in**. The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
2. Bid document may be purchased online from 19.02.2025 (17:30 hrs.) and last date for online bid submission is **10.03.2025 (17:00 hrs.)**
3. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and SBD for PMGSY Works (June-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/118834/2025 R-50614/2025

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधीन)
तृतीय तल, विकास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्र. 2377 दिनांक 19.02.2025

विज्ञप्ति

प्राधिकरण मुख्यालय एवं संचालित क्षेत्रीय कार्यालय/परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों हेतु निम्नानुसार रिक्त पदों हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. मुख्य महाप्रबंधक - 08 पद (प्रतिनियुक्ति/सेवा-निवृत्ति उपरांत संविदा)
2. महाप्रबंधक - 16 पद (प्रतिनियुक्ति/सेवा-निवृत्ति उपरांत संविदा)
3. लेखाधिकारी - 18 पद (प्रतिनियुक्ति)

पूर्णत: भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम दिनांक 12.03.2025 है।** इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय बेवसाइट **mprrda.org/default.html** पर उपलब्ध है। प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को एवं चयन की समस्त प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

म.प्र. माध्यम/118891/2025 R-50618/25 **मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड, संभाग क्रमांक-03, भोपाल-462003
Mobile No. : 9425601545, ई-मेल : mpphidcbpl3@gmail.com

क्र.-मप्रपुआअविनि/186/पर्य/भोपाल-03/तशा/2025 भोपाल, दि. : 21.02.25

प्रेस विज्ञप्ति

भोपाल संभाग-3 के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विभिन्न मरम्मत कार्य जिला शाजापुर हेतु निविदा क्रमांक-14/2024-25 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक-404407) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 07.03.2025 सायं 5:00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते है।

म.प्र. माध्यम/118926/2025 R-50619/2025 **परियोजना यंत्री**

कृषि महाविद्यालय रीवा में 12 करोड़ से अधिक लागत के किये जायेंगे विकास कार्य

रीवा, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कृषि महाविद्यालय परिसर रीवा में कन्या छात्रावास भवन तथा श्रीअन्न प्रसंस्करण एवं भण्डारण भवन का लोकार्पण किया। इनका निर्माण एक करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से कराया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा कृषि महाविद्यालय 1952 से स्थापित है। इसके भवन निर्माण तथा अधोसंरचना विकास के अन्य कार्यों की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए बनायी गयी 12 करोड़ 37 लाख रुपये की कार्ययोजना विश्वविद्यालय से मंजूरी मिलने के बाद शीघ्र लागू होगी। महाविद्यालय में नये संकायों के खोलने, प्राध्यापकों की नियुक्ति तथा शोध के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि कृषि महाविद्यालय को कुछ महीने पहले सुन्दर सड़क का उपहार दिया गया है इसमें शीघ्र ही स्ट्रीट लाइट लगायी जायेंगी।

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला झाबुआ (म.प्र)

क्रमांक/1258/निर्माण/2024-25/1285 झाबुआ, दिनांक : 14.02.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से भवन निर्माण हेतु प्रमुख अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा जारी भवन एवं विद्युत कार्य हेतु एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील एवं प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा जारी सड़क एवं पुल एस.ओ.आर. दिनांक 25.03.2022 से प्रभावशील एवं आज दिनांक तक के संशोधनों सहित निम्नलिखित विकासखण्डों में विस्तृत निविदा के अन्तर्गत परिशिष्ट में अंकित विभागीय संस्थाओं में आवश्यक संधारण मरम्मत एवं नवीन लघुमूल निर्माण कार्य इस हेतु परिशिष्ट विवरण के अनुरूप ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारियां **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।

विभागीय संस्थाओं में आवश्यक संधारण मरम्मत एवं नवीन लघुमूल निर्माण कार्य विवरण, परिशिष्ट

क्र.	पोर्टल क्रमांक	संस्था संख्या सहित कार्य का संक्षिप्त विवरण	विकास-खण्ड	ठेके की अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
		ग्रुप-ए					
1.	2025_TAD_402887	विकास खण्ड झाबुआ अधिन संचालित विभागीय शैक्षणिक/आवासीय संस्थाओं संख्या 6 में संधारण/मरम्मत/लघु निर्माण कार्य	झाबुआ	5074935	50750	10000	4 माह वर्षाकाल सहित (नवीन शैक्षणिक सत्र पूर्व)
		ग्रुप-बी					
2.	2025_TAD_402889	विकास खण्ड रामा अधिन संचालित विभागीय शैक्षणिक/आवासीय संस्थाओं संख्या 7 में संधारण/मरम्मत/लघु निर्माण कार्य	रामा	2643122	50000	5000	
		ग्रुप-सी					
3.	2025_TAD_402890	विकास खण्ड रानापुर अधिन संचालित विभागीय शैक्षणिक/आवासीय संस्थाओं संख्या 7 में संधारण/मरम्मत/लघु निर्माण कार्य	रानापुर	2960899	50000	5000	
		ग्रुप-डी					
4.	2025_TAD_402891	विकास खण्ड मेघनगर अधिन संचालित विभागीय शैक्षणिक/आवासीय संस्थाओं संख्या 4 में संधारण/मरम्मत/लघु निर्माण कार्य	मेघनगर	2866238	50000	5000	
		ग्रुप-ई					
5.	2025_TAD_402892	विकास खण्ड थांदला अधिन संचालित विभागीय शैक्षणिक/आवासीय संस्थाओं संख्या 5 में संधारण/मरम्मत/लघु निर्माण कार्य	थांदला	2971742	50000	5000	
		ग्रुप-एफ					
6.	2025_TAD_402894	विकास खण्ड पेटलावद अधिन संचालित विभागीय शैक्षणिक/आवासीय संस्थाओं संख्या 6 में संधारण/मरम्मत/लघु निर्माण कार्य	पेटलावद	4669202	50000	5000	

TOTAL- 21186138

नोट :-

- परिशिष्ट में अंकित संस्थाओं के कार्यों से संबंधित निविदाओं को वेबसाइट पर ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 07.03.2025 समय सायं 5.30 बजे तक** निर्धारित है। (Tender Document) वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** के माध्यम से क्रय किया जावेगा।
- कार्य संबंधी विस्तृत विवरण एवं निविदा की शर्तें आदि वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** या सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ के कार्यालय में देखी जा सकती है।
- समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें। शीघ्रताशीघ्र बिड जमा करें। वेबसाइट में किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- वित्तीय प्रस्ताव किसी भी स्थिति में ऑफलाइन (हार्ड कॉपी में) मान्य नहीं होगा। यदि वित्तीय प्रस्ताव मोहरबंद लिफाफे में या किसी भी प्रकार से ऑफलाइन दिया गया तो वह बिड अमान्य कर दी जावेगी।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ

जी-23246/50605/2025

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ई-मेल : ce tender.wrdmp@gmail.com
फोन : 0755-2767635, फैक्स : 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक-1131/2024-25/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक : 17.02.2025**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 13.03.2025 को 17:30 बजे तक** क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख में)
1.	2025_WRD_402568	**टर्न की पद्धति पर :-** डिण्डौरी मध्यम माइक्रो परियोजना अंतर्गत डिण्डौरी बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	डिण्डौरी	35664.03
2.	2025_WRD_402571	**टर्न की पद्धति पर :-** खरमेर मध्यम माइक्रो परियोजना अन्तर्गत खरमेर बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	डिण्डौरी	27807.30

जी-23221/50602/2025 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ई-मेल : ce tender.wrdmp@gmail.com
फोन : 0755-2767635, फैक्स : 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक-1130/2024-25/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक : 17.02.2025**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 13.03.2025 को 17:30 बजे तक** क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख में)
1.	2025_WRD_402564	**टर्न की पद्धति पर :-** लवानी (केशरपुरा) तालाब योजना (नहर रहित) का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	धार	193.82
2.	2025_WRD_402566	मण्डल कार्यालय रतलाम में कार्यालय भवन का निर्माण एवं नीमच में एफ एवं जी टाइप क्वार्टर का निर्माण कार्य।	नीमच	254.17
3.	2025_WRD_402567	चकरपुर सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित (सेमरामेढ़ा से मसनिया) 11 के.व्ही. लाइन सहित डी.टी.आर. के प्रतिस्थापन का कार्य, समस्त सामग्री एवं मजदूरी सहित।	सागर	95.09

जी-23223/50603/2025 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र, जबलपुर

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED OFFICE
इंदिरा गांधी मार्ग, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर (म.प्र.) पिन-482001
Phone No. : 0761-2621541, E-mail : cepwdcentral@mp.nic.in

निविदा सूचना क्रमांक-09/सा/2024-25 जबलपुर, दिनांक : 18.02.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के मार्फत निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने पर वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे।

स. क्र.	टेण्डर आई.डी.	जिला/ संभाग	कार्य का नाम	आमंत्रण	ठेके की अनुमा. राशि (लाख में)	अमानत राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र राशि	समया-वधि
1.	2025_ PWDRB_ 403645_1	सिवनी	उपसंभाग क्र.-2 सिवनी अंतर्गत कुरई नर्सरी से हरदुली मार्ग लंबाई 2.80 कि.मी. एवं मलारा से जनमखारी मार्ग लंबाई 4.10 कि.मी. के निर्माण कार्य मय विद्युत कार्य सहित।	प्रथम	661.32 लाख	6,61,500/-	20,000/-	09 माह वर्षाऋतु सहित
2.	2025_ PWDRB_ 403648_1	छिंदवाड़ा	आयोजना मद अंतर्गत बाघोड़ा लोधीखेड़ा मार्ग लं. 7.30 कि.मी. का पुर्ननिर्माण कार्य, मय विद्युतीकरण पोल शिफ्टिंग एवं झूलते हुये विद्युत तारों की उंचाई बढ़ाने कार्य सहित।	प्रथम	657.12 लाख	6,57,200/-	20,000/-	09 माह वर्षाऋतु सहित

टीप:- निविदा का विस्तृत विवरण (टेण्डर डाक्यूमेंट) म.प्र. शासन की निविदा पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि 06.03.2025 समय 5:30 PM तक** है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता
जी-23280/50606/2025 लो.नि.वि. जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश सूचना

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अंतर्गत सत्र 2023-24 के विभिन्न स्ववित्तीय पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन दिनांक 05.02.2025 से उपलब्ध होंगे आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 24.02.25 सायं 05:00 बजे तक** निर्धारित है। आवेदन संबंधित सूचना वेबसाइट **www.gmcratlam.org** पर उपलब्ध रहेगी

जी-23210/50601/2025

कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन)
लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, प्लाट नं.-27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं.-04/2025/निविदा/सा/ मु.अ.भ./ भोपाल, दिनांक : 10.02.2025

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

स. क्र.	पोर्टल टेंडर क्र.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
1.	2025_ PWPIU_ 401840_1	शासकीय माध्यमिक शाला भवन हण्डिया जिला हरदा का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	हरदा	41.13	50000	5000	08 माह वर्षाकाल सहित
2.	2025_ PWPIU_ 401878_1	शासकीय माध्यमिक शाला भवन मसनगांव जिला हरदा का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	हरदा	41.13	50000	5000	08 माह वर्षाकाल सहित
3.	2025_ PWPIU_ 402702_1	जिला रायसेन में संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण कार्य (बैलेंस वर्क)	रायसेन	528.95	582950	15000	12 माह वर्षाकाल सहित
4.	2025_ PWPIU_ 401912_1	शासकीय हाई स्कूल भवन बरनावद जिला शाजापुर का निर्माण कार्य।	शाजापुर	114.45	114450	12500	12 माह वर्षाकाल सहित
5.	2025_ PWPIU_ 402410_1	अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन गंजबासौदा जिला विदिशा (प्रथम आमंत्रण)	विदिशा	98.30	98300	10000	12 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 10.02.2025 समय 10.30 से दिनांक 25.02.2025 समय 05.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता (भवन)
जी-23230/50604/2025 लोक निर्माण विभाग, भोपाल

प्रदेश में 5 वर्षों में मध्यम एवं कमजोर वर्ग के लिये बनेंगे 10 लाख आवास

भोपाल, प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में शहरी क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिये 10 लाख आवासों का निर्माण किया जायेगा। इन आवासों के निर्माण में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस राशि में केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुमानित अनुदान राशि 23 हजार 25 करोड़ रुपये प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

योजना में पात्र हितग्राही परिवारों के लिये हर मौसम के अनुकूल आवासों के निर्माण के साथ समुचित अधोसंरचना जैसे- सड़क, जल प्रदाय, सीवेज, पार्क तथा सामाजिक अधोसंरचना के रूप में आंगनवाड़ी, प्राथमिक शाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विकसित किये जायेंगे। राज्य शासन द्वारा सभी पात्र हितग्राही परिवारों को आवास दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू 2.0) में अब तक करीब 2 लाख 90 हजार हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। योजना का क्रियान्वयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

पीएमएवाई-यू 2.0 में जिन 4 घटकों में लाभान्वित किया जायेगा, उनमें आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के पात्र हितग्राही होंगे। बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (बी.एल.सी.) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राही अपनी स्वयं की भूमि पर आवास का निर्माण कर सकेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड पार्टनरशिप (ए.एच.पी.) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितग्राहियों को नगरीय निकायों, राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियों तथा निजी बिल्डर/डेवलपर्स द्वारा आवासों का निर्माण कर प्रदान किया जायेगा। इसके अंतर्गत निजी डेवलपर द्वारा परियोजना में हितग्राहियों द्वारा आवास क्रय करने पर रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर (आर. एच.व्ही.) प्रदान किया जायेगा। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ए.आर.एच.) में कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर और निराश्रितों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों के लिये किराये के आवास बनाकर उपलब्ध कराये जायेंगे। इन्ट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम (आई.एस.एस.) में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं एमआईजी वर्ग के पात्र परिवारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा।

दिशा-निर्देश अनुसार होगा क्रियान्वयन

पीएमएवाई-यू 2.0 में सिंगल यूमेन, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, कल्याण महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरियता दी जायेगी। इसी के साथ योजना में सफाईकर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना में चिह्नित स्ट्रीट वेंडर्स, पीएम विश्वकर्मा योजना के विभिन्न कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों और बस्ती एवं चाल के निवासियों पर योजना में विशेष ध्यान दिया जायेगा। योजना में बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त करने की दिशा में भूमि को संसाधन के रूप में पीपीपी मॉडल पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी जायेगी। ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितग्राहियों का अंशदान कम करने के लिये पूर्वानुसार क्रॉस सब्सिडी मॉडल को क्रियान्वित किया जायेगा। भूमिहीन पात्र हितग्राही परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति भी दी गई है। बीएलसी वर्ग के हितग्राहियों को प्रति आवास 2 लाख 50 हजार रुपये अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थी परिवारों द्वारा आवास के निर्माण के चरणों का स्वयं जियो टैगिंग का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अविवाहित कमाऊ वयस्क सदस्यों को पृथक से लाभ प्रदान करने के प्रावधान को समाप्त कर एक हितग्राही परिवार में पति-पत्नी, अविवाहित बेटे-बेटियों को शामिल किया गया है।

जर्मनी से कल्चरल और एजुकेशनल टूर पर आयेंगे पर्यटक

भोपाल, जर्मन ट्रैवल एसोसिएशन (डीआरवी) का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मध्यप्रदेश के पर्यटन बाजार में विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला से एमपी टूरिज्म बोर्ड में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल पांच दिवसीय फेमिलियराइजेशन (फैम) टूर के तहत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और अनुभवों का अनुभव करने आया है।

प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल का यह टूर जर्मनी ट्रैवल एसोसिएशन के साथ प्रदेश के ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स के समन्वय को बढ़ाएगा। जर्मनी से आने वाले पर्यटकों की रुचि अनुरूप प्रदेश के ट्रैवल और टूर ऑपरेटर ट्रैवल प्लान बनायेंगे। प्रतिनिधिमंडल के सहयोग से जर्मनी से कल्चरल और शैक्षणिक टूर के माध्यम से पर्यटकों को मध्यप्रदेश आमंत्रित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जर्मन ट्रैवल एसोसिएशन (डीआरवी) के अध्यक्ष श्री नॉर्बर्ट फिबिग और राजनीतिक मामलों एवं आउटबाउंड ट्रैवल प्रमुख श्री वोल्कर एडम्स कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल को विश्व धरोहर स्थल भीमबैटका, सांची, खजुराहो, ट्राइबल म्यूजियम, ओरछा, तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कराया जा रहा है।

बीज संघ के उत्पाद नये ब्रॉन्ड नेम और आकर्षक 'लोगो' के साथ करें विक्रय

भोपाल, बीज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज के विपणन का कार्य नये ब्रॉन्ड नेम के साथ किया जाए इसके लिये आकर्षक लोगो तैयार किया जाए यह बात सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय में राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ के संचालक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

श्री सारंग ने कहा कि पैक्स, अन्य सहकारी संस्थाओं तथा निजी व्यवसायियों के माध्यम से स्थानीय कृषकों को प्रमाणित बीज विपणन का कार्य हो। उन्होंने विपणन विशेषज्ञ एवं बीज उत्पादन से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ की सेवायें लेने को भी कहा। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग और पैकेजिंग पर आवश्यक ध्यान दिया जाये। इस कार्यवाही से पैक्स के 32 लाख कृषक सदस्यों, बीज सहकारी संस्थाओं के सदस्यों एवं अन्य कृषकों को बीज संघ द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा। श्री सारंग ने कहा कि बीज सोसायटियों को नवाचार विंग से जोड़े और बीज सोसायटियों की रेटिंग भी की जायें। उन्होंने कहा कि बिजनेस मॉड्यूल तैयार करें और बिजनेस डेवलपमेंट का सेटअप बनायें।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

केन्द्रीय बजट 2025-26

1. केन्द्रीय बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों की पहचान की गई है?
अ. चार ब. दो
स. तीन द. पांच
उत्तर- अ. चार
व्याख्या- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात

2. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से कितने किसान लाभान्वित होने वाले हैं?
अ. 1 करोड़ ब. 1.7 करोड़
स. 2 करोड़ द. 2.7 करोड़
उत्तर- ब. 1.7 करोड़

3. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में कितने निम्न उत्पादन वाले जिलों को सम्मिलित किया जायेगा?
अ. 100 ब. 125
स. 150 द. 200
उत्तर- अ. 100

4. दालों में आत्मनिर्भर मिशन इस बजट में शुरू होना प्रस्तावित है। इस मिशन में कौन-सी दालों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
अ. अरहर ब. उड़द
स. मसूर द. उपरोक्त सभी
उत्तर- द. उपरोक्त सभी

5. संशोधित ब्याज योजना के तहत अब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितने लाख रुपये का ऋण दिया जा सकेगा?
अ. 2 लाख ब. 5 लाख
स. 6 लाख द. 7 लाख
उत्तर- ब. 5 लाख

6. इस बजट में एमएसएमई को गारंटी के साथ दिये जाने वाले ऋण को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है?
अ. 10 करोड़ ब. 7 करोड़
स. 8 करोड़ द. 9 करोड़
उत्तर- अ. 10 करोड़

7. वित्तीय वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
अ. 4.5 ब. 4.6
स. 4.8 द. 5
उत्तर- स. 4.8

8. वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
अ. 4.4 ब. 4.6
स. 4.8 द. 5
उत्तर- अ. 4.4

9. मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिये लघु-मध्यम एवं वृहद उद्योग को शामिल कर कौन-सा नया मिशन प्रारम्भ किया गया है?
अ. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण मिशन
ब. राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन
स. राष्ट्रीय उद्योग मिशन
द. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- ब. राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन

10. इस बजट में निवल कर प्राप्तियां कितने लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है?
अ. 34.96 ब. 30.96
स. 28.37 द. 20.3
उत्तर- स. 28.37

11. केन्द्रीय बजट में सकल बाजार उधारियां कितने लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है?
अ. 14.82 ब. 20.82
स. 17.38 द. 18.32
उत्तर- अ. 14.82

12. इस बजट में राज्यों की भागीदारी से 'ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण' एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसके पहले चरण में कितने विकासशील कृषि जिले सम्मिलित होंगे?
अ. 80 ब. 100
स. 120 द. 130
उत्तर- ब. 100

13. दलहनों में आत्मनिर्भरता कार्यक्रम के तहत कौन-सी केन्द्रीय एजेंसी/एजेंसियां कृषकों से दालें क्रय करेंगी?
अ. नेफेड
ब. एनसीसीएफ
स. उपरोक्त दोनों
द. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- स. उपरोक्त दोनों

14. इस बजट में घोषित मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जायेगा?
अ. बिहार ब. उत्तरप्रदेश
स. मध्यप्रदेश द. पं. बंगाल
उत्तर- अ. बिहार

15. राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस मिशन के तहत कितने बीजों की किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है?
अ. 75 ब. 100
स. 120 द. 150
उत्तर- ब. 100

16. कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिये कितने वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है?
अ. 2 ब. 3
स. 5 द. 7
उत्तर- स. 5

17. 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया का संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा?
अ. असम ब. बिहार
स. त्रिपुरा द. मिजोरम
उत्तर- अ. असम (असम में नामरूप में यह स्थापित होगा)

18. उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिये पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले कितने लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किये जायेंगे?
अ. 5 ब. 10
स. 15 द. 20
उत्तर- ब. 10

19. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की पहली बार उद्यमी बनने वाले कितनी महिला उद्यमियों को अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण उपलब्ध करवाया जावेगा?
अ. 5 ब. 6
स. 7 द. 8
उत्तर- अ. 5

20. फोकस उत्पाद स्कीम किस क्षेत्र के लिये प्रारंभ की गई है?
अ. मसाला
ब. फुटवियर और लेदर
स. पेपर
द. उपरोक्त सभी
उत्तर- ब. फुटवियर और लेदर

21. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस राज्य में प्रस्तावित है?
अ. महाराष्ट्र ब. उत्तरप्रदेश
स. बिहार द. उड़ीसा
उत्तर- स. बिहार

22. अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालायें स्थापित की जाना प्रस्तावित हैं?
अ. 20000 ब. 25000
स. 30000 द. 50000
उत्तर- द. 50000

23. मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिये युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिये कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जायेंगे?
अ. 5 ब. 6
स. 7 द. 10
उत्तर- अ. 5

24. शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिये कितने रुपये का परिव्यय रखा गया है?
अ. 200 ब. 500
स. 700 द. 900
उत्तर- ब. 500

25. नई कर व्यवस्था के तहत अब कितने लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगना सम्भावित है?
अ. 12 ब. 12.75
स. 13 द. 15
उत्तर- ब. 12.75 वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये है।

26. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक बढ़ाना प्रस्तावित है?
अ. 100 ब. 74
स. 80 द. 90
उत्तर- अ. 100 (वर्तमान में यह 74% है जिसे बढ़ाकर 100% करना प्रस्तावित है)

27. स्टार्टअप्स के लिये कितने हजार करोड़ रुपये की राशि के साथ नया फंड बनाया जाना प्रस्तावित है?
अ. 8 ब. 10
स. 12 द. 15
उत्तर- ब. 10

28. इस बजट में एमएसएमई के लिये वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः कितने गुना बढ़ाया जायेगा?
अ. 2.5,2 ब. 2, 2.5
स. 5, 5 द. 2, 2
उत्तर- अ. 2.5,2

29. केन्द्रीय बजट ने किस क्षेत्र को रोज़गार प्रेरित विकास के रूप में स्थापित किया है?
अ. बीमा ब. बैंकिंग
स. पर्यटन द. उपरोक्त सभी
उत्तर- स. पर्यटन

30. कितने वर्षों में सरकार सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केन्द्र स्थापित करेगी?
अ. 5 ब. 4
स. 3 द. 2
उत्तर- स. 3 (वर्ष 2025-26 में 200 केन्द्र स्थापित होंगे।)

31. 2033 तक कितने विकसित लघु माड्यूलर रियक्टर्स (एसएमआर) संचालित करने का प्रस्ताव है?
अ. 2 ब. 3
स. 4 द. 5
उत्तर- द. 5
व्याख्या- 20 हजार करोड़ के आवंटन के साथ इनके अनुसंधान एवं विकास के लिये परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जायेगा।

32. 25 हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना की घोषणा की गई है इसमें सरकार की भागीदारी कितने प्रतिशत है?
अ. 49 ब. 51
स. 50 द. 100
उत्तर- अ. 49

33. किस राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई है?
अ. महाराष्ट्र ब. कर्नाटक
स. आंध्रप्रदेश द. बिहार
उत्तर- द. बिहार

34. चुनौती मोड के जरिये राज्यों की भागीदारी से देश में कितने शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जावेगा?
अ. 50 ब. 60
स. 70 द. 100
उत्तर- अ. 50

35. शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिये भारत मिशन बनाया जावेगा। इसमें कितने करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जावेगी?
अ. 5 ब. 4
स. 3 द. 1
उत्तर- द. 1

36. इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिये ब्याज पर कटौती की सीमा कितनी कर दी गई है?
अ. 50, 000
ब. 1,00,000
स. कोई परिवर्तन नहीं
द. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- ब. 1,00,000

37. किराये से प्राप्त आय में टीडीएस कटने की सीमा कितने रुपये की गई है?
अ. 2.5 ब. 3.00
स. 6.00 द. 10.00
उत्तर- स. 6.00

38. प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिये राज्यों के लिये एक निवेश अनुमूल सूचकांक का शुभारम्भ किस वर्ष होना संभावित है?
अ. 2025 ब. 2026
स. 2027 द. 2028
उत्तर- अ. 2025

39. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तीय समाधानों के लिये किस संयुक्त प्लेटफॉर्म की स्थापना प्रस्तावित है?
अ. भारतीय व्यापार
ब. भारत ट्रेडनेट
स. इंडियन बिजनेस
द. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- ब. भारत ट्रेडनेट

40. वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
अ. 1.9 ब. 1.5
स. 2.0 द. 2.1
उत्तर- अ. 1.9

41. केन्द्रीय व्यय में सबसे अधिक खर्च वाली मद है?
अ. ब्याज अदायगी
ब. केन्द्रीय क्षेत्र की योजना
स. करों एवं शुल्क में राज्यों की हिस्सा
द. पेंशन
उत्तर- स. करों एवं शुल्क में राज्यों की हिस्सा (22% इस मद में खर्च किया जाता है)

42. केन्द्रीय आय में अधिक आय किस मद से आती है?
अ. उधार और अन्य देयताओं
ब. आयकर
स. जीएसटी
द. निगमकर
उत्तर- अ. उधार और अन्य देयताओं (24% आय इस मद से आती है।)

- डॉ. माया राठी
(लेखिका, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, भोपाल में अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका हैं।)

प्रदेश में रेलवे-सड़क मार्गों से जुड़ी सभी एजेंसी समन्वय बनाकर बेहतर व्यवस्था रखें

भोपाल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रदेश में रेलवे-सड़क मार्गों से जुड़ी सभी एजेंसियों को समन्वय बनाकर यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री जे.एन. कंसोटिया, सचिव गृह श्री गौरव राजपूत और परिवहन सचिव श्री मनीष सिंह मौजूद थे। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेलवे, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों से जिलों में की गयी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

सेंट्रल कंट्रोल-रूम की हो व्यवस्था

मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी दिनों में महाशिवरात्रि को देखते हुए प्रयागराज से जुड़े मार्गों पर भीड़ का दबाव बना रहेगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों के बीच समन्वय के लिये सेंट्रल कंट्रोल-रूम की व्यवस्था हो, जहां महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। उन्होंने कहा कि भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिये पुलिस और रेलवे फोर्स के साथ वॉलेंटियर्स का सहयोग लिया जाये। उन्होंने भीड़ के दबाव को कम करने के लिये जिलों में की गयी होल्डिंग सेंटर की व्यवस्था की जानकारी ली।

श्री जैन ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के पास बेरीकेड्स लगाकर व्यवस्था की जाये। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से कहा कि रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन की क्षमता के अनुसार यात्रियों का प्रवेश सुनिश्चित हो। रेलवे स्टेशनों में यात्रियों की सुविधा के लिये एनाउंसमेंट की स्पष्ट सुविधा हो। स्टेशन प्लेटफार्म पर यात्रियों के खान-पान के साथ सुलभ सुविधा की व्यवस्था हो।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी

रमन प्रभाव का दुनिया मानती है लोहा

"हमेशा सही सवाल पूछें, फिर देखना प्रकृति अपने सभी रहस्यों के द्वार खोल देगी।" ये विचार डॉ. सीवी रमन के हैं। जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान देश को ठोस विश्वास देता है। जब कोई वैज्ञानिक विज्ञान में नया सिद्धांत गढ़ता है और उन सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिलती है, तो उनकी सफलता राष्ट्र की सफलता बन जाती है। आज भी जब-जब रमन प्रभाव का ज़िक्र होता है तब-तब भारत के नाम का ज़िक्र होता है।

इस बार की थीम क्या है?

भारत सरकार ने वर्ष 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। इस दिन सर सीवी रमन ने 'रमन प्रभाव' की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर थीम-आधारित विज्ञान गतिविधियां पूरे देश में चलायी जाती हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाना देना, विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और जनता में वैज्ञानिक स्वभाव पैदा करके नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और एक सकारात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्कृति का निर्माण करना है। इस वर्ष 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस "Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science & Innovation for VIKSIT BHARAT" यानी 'विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना' थीम के तहत मनाया जा रहा है। वहीं विज्ञान दिवस-2024 की थीम "विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक' तय की गई थी।

समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य, समाज में विज्ञान की अहमियत को समझाना और वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस को बढ़ावा देना है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और प्रासंगिकता को भी दिखाने के लिए यह दिवस अहम है।

कौन थे सीवी रमन?

"शिक्षा का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिये सक्षम बनाना है।" ऐसे विचार को समाज में रखने वाले सीवी रमन सीखने-सिखाने तथा तर्कसंगत सवाल करने के पक्षधर थे। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकटरमन था। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर, 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर गणित और भौतिकी के लेक्चरर थे इसलिए गणित और भौतिकी का माहौल इन्हें घर ने ही मिला था। पिता से ही रमन में विज्ञान एवं शिक्षण के प्रति लगाव पैदा हुआ था। सीवी रमन ने 11 साल की आयु में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी, 13 साल में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की और 16 साल की आयु में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने भौतिकी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय से बेहतरीन अंकों के साथ गणित में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की थी। डिग्री प्राप्त करने के बाद वे भारतीय वित्त विभाग में नौकरी करने लगे, लेकिन कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में शोध करना जारी रखा था। हालांकि बाद में रमन ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर बन गए। यहीं से रमन के तमाम शोध कार्य पूरे हुए थे।

रमन प्रभाव की कहानी

स्नातकोत्तर की पढ़ाई के दौरान सीवी रमन ने प्रकाश के व्यवहार पर आधारित

अपना पहला शोध-पत्र लिखा था। उन्होंने अपने एक प्रोफेसर को शोध-पत्र पढ़ने के लिये भेजा था, लेकिन व्यस्तता के कारण उनके प्रोफेसर शोध-पत्र को नहीं पढ़ पाए। इसके बाद रमन ने एक प्रसिद्ध पत्रिका को शोधपत्र भेज दिया, जिस पर उनका शोध-पत्र प्रकाशित हुआ। इसके बाद ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक बैरन रेले ने उस पत्र को पढ़ा। रमन के शोध-पत्र से रेले काफी प्रभावित हुए, उन्होंने रमन को पत्र लिखकर उनकी तारीफ की। रमन का शोध-पत्र इतना अच्छा था कि बैरन रेले शोध-पत्र की मौलिकता एवं निष्कर्ष से प्रभावित हो गए और सीवी रमन को प्रोफेसर समझ बैठे थे, उन्होंने रमन को लिखे पत्र में रमन को प्रोफेसर कहकर संबोधित किया था।

वर्ष 1921 में सीवी रमन जल जहाज से ब्रिटेन जा रहे थे। उन्होंने भूमध्य सागर में पानी के सुंदर नीले रंग को देखा। उस समय उनको समुद्र के पानी के नीले रंग पर शक हुआ। जब वह भारत वापस आने लगे तो अपने साथ कुछ उपकरण लेकर आए। सीवी रमन ने उन उपकरणों की मदद से आसमान और समुद्र का अध्ययन किया। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि समुद्र भी सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, जिससे समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। उन्होंने ठोस, द्रव और गैस में प्रकाश के विभाजन पर शोध जारी रखा। आखिरकार वह जिस नतीजे पर पहुंचे वही रमन प्रभाव कहलाया। जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई।

रमन प्रभाव बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है तो इस प्रक्रिया में प्रकाश का कुछ हिस्सा स्कैटर कर जाता है यानी, बिखर जाता है। बिखरे हुए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य समान रहती है किंतु उनमें से कुछ हिस्से की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। इसे रमन प्रभाव से जाना गया। प्रकाश के क्षेत्र में उनके इस कार्य के लिये वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश के क्षेत्र में किये गए उनके कार्य का आज भी कई क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। रमन की स्पेक्ट्रोस्कोपी का ज़िक्र डॉक्टर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1929 में रॉयल सोसाइटी के अपने अध्यक्षीय भाषण में भी किया था। रमन को रॉयल सोसाइटी के द्वारा एकनॉलेज्ड किया गया था और उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की गई थी।

इसके बाद वर्ष 1932 में उन्होंने सूरी भगवंतम के साथ मिलकर क्वांटम फोटॉन स्पिन की खोज की, तबला एवं मृदंगम जैसे भारतीय ढोल की ध्वनि की हार्मोनिक प्रकृति की भी उन्होंने जांच की। वे वर्ष 1933 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने 15 वर्षों तक कार्य किया। वह वर्ष 1948 में भारतीय विज्ञान संस्थान से सेवानिवृत्त हुए और वर्ष 1949 में बेंगलुरु में रमन अनुसंधान संस्थान बनाया। उनका संपूर्ण जीवन विज्ञान और शिक्षण को समर्पित रहा।

विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई पहलें की जा रही हैं। इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेटवर्क, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति, और आईआईटी गांधीनगर के साथ क्रिएटिव लर्निंग सेंटर शामिल हैं। मध्यप्रदेश में फार्मिंग से लेकर फायनेंस तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन तक, एजुकेशन से लेकर कम्यूनिकेशन तक विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि मध्यप्रदेश आने वाले समय में विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और इन क्षेत्रों से जुड़ी सेवाओं का नया हब बनकर देश में उभरेगा। देश की टेक्नोलॉजी में मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सुशासन के माध्यम से जन-कल्याण पर जोर दिया जा रहा है इसके लिए राज्य सरकार के विभागों में डिजिटलाइज्ड प्रणाली संचालित है। अनेक नवाचार भी हुए हैं।

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एमपीसीएसटी) मध्यप्रदेश सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय भोपाल के विज्ञान भवन में है। इस संस्थान का उद्देश्य राज्य के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का विकास करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए सामाजिक और आर्थिक उद्देशों को पूरा करना है।

वर्तमान युग में नई प्रौद्योगिकी और तकनीकी का उपयोग जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। ऐसी अनेक नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों तथा भू-प्रबंधन, कृषि, उद्योग, उर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खनिज, हितग्राहीमूलक योजनाओं, अधोसंरचना, इत्यादि में किया जाकर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

- रश्मि रंजन

(लेखिका, सम-सामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)

मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति

शराबबंदी को अमल में लाने का प्रभावी कदम

विगत 24 जनवरी को देवी अहिल्या बाई होल्कर की नगरी महेश्वर में कैबिनेट ने धर्मनगरियों में शराबबंदी का निर्णय लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी कैबिनेट का यह निर्णय अपनी विरासत के सम्मान के साथ निर्माण की नई पहल है।

प्रदेश के 19 स्थलों पर शराबबंदी के निर्णय ने समाज में होने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत दिया है। पवित्र तीर्थ स्थलों से नकारात्मक पदार्थ की समाप्ति से सकारात्मक भाव की वृद्धि होगी। यहां की पवित्रता बढ़ेगी, धार्मिक स्थल पर आने वाले श्रद्धालु अच्छी अनुभूमि लेकर जायेंगे। इसके प्रभावी अमल से आने वाली पीढ़ी को नशामुक्ति का संदेश जायेगा और वे नशे से दूर रहेंगे।

महेश्वर कैबिनेट में लिये गये निर्णय को अमल में लाने के लिए मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति 2025-26 जारी की गयी। इस नीति को अमल में लाकर प्रदेश के जिन पवित्र क्षेत्रों में शराबबंदी की घोषणा की गयी थी। उन क्षेत्रों में मदिरा दुकानों को 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया जाएगा। इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर, बांदकपुर शामिल हैं। नई नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वाइन आउटलेट के न तो लाइसेंस जारी किए जाएंगे और न ही उन्हें चलाने की अनुमति होगी।

नये जिलों में मदिरा दुकानों का संचालन एवं प्रशासन वहां के जिला कलेक्टरों के अधीन किया जाएगा। जनजातीय बंधुओं के हित में वाइन शॉप पर वाइन एवं हेरिटेज मदिरा का विक्रय किया जा सकेगा। एयरपोर्ट काउंटर पर भी हेरिटेज मदिरा विक्रय की अनुमति रहेगी। किसी भी मदिरा दुकान के परिसर में मदिरापान की अनुमति नहीं होगी।

नई आबकारी नीति के अनुसार जिलों में जिला निष्पादन समिति गठित की जायेगी। जिला निष्पादन समिति मदिरा दुकानों का विस्थापन कर जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोलने, दुकान का पोर्टेशियल क्षेत्र निर्धारित करने, दुकानों का आरक्षित मूल्य निर्धारण करने, मदिरा दुकानों के एकल समूह का गठन या पुनर्गठन करने, शासन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दुकानों को चलाने संबंधी सभी कार्य करेगी।

वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि उपरांत वर्ष 2025-26 के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2025-26 में सर्वप्रथम वर्तमान वर्ष 2024-25 के अनुज्ञप्तिधारियों को नवीनीकरण का अवसर प्रदान किया गया है। तदोपरांत लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। नवीनीकरण एवं लॉटरी आवेदन पत्र से जिले के आरक्षित मूल्य के 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक के राजस्व की प्राप्ति होने पर नवीनीकृत किया जावेगा। जरूरत पड़ने पर ई-टेण्डर और ई-टेण्डर कम ऑक्शन की पद्धति को अपनाया जायेगा।

सभी मदिरा दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें स्थापित की जायेंगी, मशीन के माध्यम से समस्त प्रकार की मदिरा बोतल पर चस्पा एक्साइज एडेहसिव लेबल (ईएएल) को अनिवार्यत: स्कैन कर ही बिलिंग होगी और बेचा जा सकेगा। जो व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड है वह मदिरा दुकान अथवा समूह के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। विदेशी मदिरा भण्डागार को स्मार्ट वेयरहाउस में बदला जायेगा। विदेशी मदिरा भण्डागार पर बायोमेट्रिक ई-लॉक का प्रावधान किया गया है।

भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट के समान अन्य व्यवसायिक उड़ाने संचालित करने वाले एयरपोर्ट पर भी विदेशी मदिरा काउंटर के लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी। आगमन एवं प्रस्थान द्वार पर एक-एक काउण्टर खोलने की अनुमति दी जा सकेगी।

वर्ष 2025-26 में रेस्तरां बार की एक नवीन श्रेणी "लो एल्कोहालिक बीवरेज बार" प्रारंभ की जाएगी। इस लायसेंस के अंतर्गत रेस्तरां में सिर्फ बीयर, वाइन एवं 'रेडी-टू-ड्रिंक" श्रेणी की विदेशी मदिरा जिसमें अल्कोहल की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत V/V तक ही हो, के सेवन की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के स्पिरिट का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

वर्ष 2025-26 से व्यवसायिक किस्म के आयोजनों हेतु प्रासांगिक अनुज्ञप्ति (एफ. एल.-5) की लायसेंस फीस की पृथक श्रेणी रहेगी। व्यवसायिक किस्म के कार्यक्रमों तथा आयोजनों जिनमें प्रवेश निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर दिया जाता है, उस दौरान मदिरा के उपयोग की अनुमति कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुसार लायसेंस फीस रहेगी।

हेरीटेज मदिरा संबंधी नीति और व्यवस्था वर्ष 2024-25 के अनुसार यथावत रहेगी। हेरीटेज मदिरा बनाने वाली इकाइयों द्वारा बनाई हेरीटेज मदिरा को राज्य शासन के वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) से मुक्त रखा जाएगा।

राज्य शासन द्वारा घोषित अंगूर प्र-संस्करण नीति में प्रदेश में फलोद्यान विस्तार एवं फल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश में उत्पादित अंगूर एवं जामुन के अतिरिक्त अन्य फलों और प्रदेश में उत्पादित तथा संग्रहित शहद से बनी वाइन का निर्माण किया जा सकेगा।

प्रदेश में उत्पादित फलों एवं शहद से प्रदेश में वाईन निर्माण करने वाली इकाइयों को उनके परिसर में वाइन के फुटकर विक्रय के लिए एक रिटेल आउटलेट स्वीकृत किया जा सकेगा। पर्यटकों के लिए वाइनरी परिसर में वाइन टेवर्न (वाइन टेस्टिंग सुविधा) की अनुमति होगी। वर्ष 2025-26 में विशेष मदिरा के निर्माण, भण्डारण, निर्यात, आयात एवं विक्रय की अनुमति विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाइयों को भी दी जा सकेगी।

मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति में जहाँ प्रदेश में घोषित धार्मिक स्थलों में शराबबंदी के निर्णय को अमल में लाया जायेगा। वहीं हैरीटेज मदिरा के विक्रय से जनजातीय बंधुओं के पारम्परिक कार्य, व्यवहार और आय को बल मिलेगा। इस नीति से मध्यप्रदेश में शराबबंदी से लेकर भविष्य की परिकल्पना के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं।

नीति में अंगूर, जामुन तथा अन्य फलों से वाइन के निर्माण को शामिल करने से प्रदेश के उद्यानिकी क्षेत्र का विस्तार होगा। कृषि तथा वन क्षेत्र बाहुल्य प्रदेश में फलोद्यान को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र और किसानों की आय बढ़ेगी और वे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से विकास की धारा में सक्रिय भूमिका निभायेंगे। इसी तरह शहद से वाइन के निर्माण को नीति में शामिल करने से ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिलेगा। नई आबकारी नीति जनजातियों, किसानों और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में एक अच्छा भविष्य निर्माण करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

हितेश शर्मा

(लेखक, समसामयिक विषयों पर लेखने करते हैं)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड

पद का नाम - इंजीनियर ट्रेनी, सुपरवाइजर ट्रेनी
पदों की संख्या - 400
योग्यता - इंजीनियर ट्रेनी के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक डिग्री तथा सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
अंतिम तिथि - 28 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://www.bhel.com

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश

पद का नाम - चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ खरीद सह भंडार अधिकारी, मुख्य आहार विशेषज्ञ, मुख्य चिकित्सा समाज सेवा अधिकारी, अस्पताल वास्तुविद, नर्सिंग अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा रिकॉर्ड अधिकारी, पर्यवेक्षक चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, लेखा अधिकारी, भंडार अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी, सहायक भंडार अधिकारी
पदों की संख्या - 25
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 05 मार्च, 2025
वेब. - https://aiimsrishikesh.edu.in

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

पद का नाम - प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर
पदों की संख्या - 66
योग्यता - संबंधित विषय में पीएचडी उपाधि होना आवश्यक है।
अंतिम तिथि - 04 मार्च, 2025
वेबसाइट - https://dhsgsu.edu.in/

केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान

पद का नाम - तकनीकी सहायक
पदों की संख्या - 22
योग्यता - मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ बीएससी या अन्य समकक्ष डिग्री
अंतिम तिथि - 01 मार्च, 2025
वेब.- https://www.clri.org/Careers

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

पद का नाम - आरक्षक (चालक), आरक्षक (चालक सह पम्प ऑपरेटर)
पदों की संख्या - 1124
योग्यता - अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा अभ्यर्थी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।
अंतिम तिथि - 04 मार्च, 2025
वेब. - https://cisfrectt.cisf.gov.in

भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान

पद का नाम - तकनीकी सहायक
पदों की संख्या - 23
योग्यता - न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा
अंतिम तिथि - 28 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://www.iict.res.in

राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान

पद का नाम - सहायक प्रोफेसर (सलाहकार), लेक्चरर (सलाहकार), क्लीनिकल सहायक (सलाहकार), प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट- प्रदर्शनकर्ता (सलाहकार), विशेष शिक्षक (सलाहकार)
पदों की संख्या - 18
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 28 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://niepmd.nic.in

भारी वाहन निर्माणी, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड

पद का नाम - सलाहकार (साइबर सुरक्षा), वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर (मैकेनिकल), डिजाइन इंजीनियर (मैकेनिकल), प्रबंधक (उत्पादन), उत्पादन इंजीनियर (मैकेनिकल), उत्पादन इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), गुणवत्ता इंजीनियर (मैकेनिकल), गुणवत्ता इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), सहायक (स्टोर)
पदों की संख्या - 32
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 28 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://avnl.co.in

एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड

पद का नाम - ग्रुप मैनेजर, सीनियर ऑफिसर, मैनेजर ऑपरेशन, कंट्रोल रूम ऑफिसर, फील्ड ऑपरेटर, मैनेजर इलेक्ट्रिकल, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल
पदों की संख्या - 31
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 02 मार्च, 2025
वेबसाइट - https://www.hplng.in

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमि.

पद का नाम - अप्रेंटिस
पदों की संख्या - 457
योग्यता - तीन वर्षीय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग
अंतिम तिथि - 03 मार्च, 2025
वेबसाइट - https://iocl.com

एनटीपीसी लिमिटेड

पद का नाम - असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव (ऑपरेशन)
पदों की संख्या - 400
योग्यता - मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में बीई/बीटेक या अन्य इंजीनियरिंग स्नातक डिग्री
अंतिम तिथि - 01 मार्च, 2025
वेबसाइट - https://ntpc.co.in

म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

पद का नाम - आईटीआई अप्रेंटिस (फिटर, वायर मेन, विद्युतकार, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर)
पदों की संख्या - 10
योग्यता - मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से आईटीआई उत्तीर्ण
अंतिम तिथि - 02 मार्च, 2025
वेब. - https://mppgcl.mp.gov.in

फैलोशिप अलर्ट

रामलिंगास्वामी रि-एंट्री फैलोशिप-2025

संस्थान का नाम - जैव प्रौद्योगिकी विभाग
योग्यता- लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायो-इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी बायोटेक्नोलॉजी विषय में अध्ययनरत विद्यार्थी
फैलोशिप की संख्या- प्रतिवर्ष 75 फैलोशिप दी जायेंगी
अंतिम तिथि - 28 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://dbtindia.gov.in

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

हमारा जिला सिवनी

जनजातीय संस्कृति, वन्य प्राणी और पर्यटन विशिष्टताओं से परिपूर्ण है सिवनी

मध्यप्रदेश विविधता से समृद्ध है। प्रदेश के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता, क्षमता और दक्षता है। यहां का प्रत्येक जिला अपना इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, उपज और अन्य क्षेत्रीय विशेषताएं लिए हुए है। 'रोज़गार और निर्माण' के 'हमारा जिला' स्तम्भ में हम मध्यप्रदेश के एक जिले से आपको परिचित करवाते हैं। इस अंक में प्रस्तुत है सिवनी जिले का परिचय-

सिवनी जिला जनजातीय बाहुल्य जिला है। जिले का नाम अधिक मात्रा में पाये जाने वाले सेऊना नामक वृक्ष के नाम पर किया गया। इस वृक्ष का उपयोग ढोलक बनाने में किया जाता है। यह जिला सतपुड़ा पर्वत के उत्तर-दक्षिण में स्थित है। यहां इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत है। जिले में मुख्य रूप से सागौन पाया जाता है। जिला मुख्यालय सिवनी नागपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 और जबलपुर नागपुर के बीच स्थित है। जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसके पड़ोसी जिलों में उत्तर दिशा की ओर जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर हैं। पूर्व दिशा की ओर बालाघाट, पश्चिम दिशा की ओर छिंदवाड़ा और दक्षिण दिशा की ओर नागपुर है। यहां से 30 किलोमीटर दूर नागपुर मार्ग पर मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम का एक होटल है जिसका रेस्टोरेंट सागौन के पत्तों से बना हुआ है।

प्रशासनिक संरचना

जिले में 8 तहसीलें हैं-सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, धनौरा, घंसौर, छपारा और कुरई। जिले के 8 विकासखंडों में सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, धनौरा, घंसौर, छपारा, कुरई शामिल हैं। इनमें 5 विकासखण्ड लखनादौन, धनौरा, घंसौर, छपारा, कुरई एवं 3 सामुदायिक विकासखण्ड, सिवनी, बरघाट, केवलारी हैं। जिले में सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन विधानसभा क्षेत्र हैं। जिले की 4 नगर पालिका सिवनी, केवलारी, लखनादौन और बरघाट हैं।

इतिहास

सिवनी जिले के नामकरण के संबंध में अनेक दंतकथायें एवं धारणायें प्रचलित हैं। इतिहास में यह जिला मंडला के गोंड राजाओं के 52 गढ़ों में से एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। नगर मुख्यालय में तीन गढ़ चावडी, छपारा और आदेगांव प्रमुख थे। गोंड राजाओं के पश्चात सन् 1700 में यह नागपुर के भोसले साम्राज्य में शामिल रहा। सत्ता का केन्द्र छपारा ही था। सन् 1774 में छपारा से बदलकर मुख्यालय सिवनी हो गया। इसी समय दीवानगढ़ी का निर्माण हुआ और सन् 1853 में मराठों के पतन के बाद यह क्षेत्र अंग्रेजी राज्य के अधीन चला गया। मुख्यालय में दीवान साहब का सिवनी ग्राम, मंगलीपेठ एवं भैरोगंज ग्राम मिलकर सिवनी नगर बना। इसके बाद सन् 1867 में सिवनी नगरपालिका का गठन हुआ। सिवनी में वनोपज हर्रा, बहेड़ा, आंवला एवं महुआ बहुतायत में होता है। लगभग 200 वर्षों के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। सिवनी जिला सन् 1956 में पुनः जिला बना।

दल सागर तालाब

गोंडवाना साम्राज्य के गोंड राजा दलपत शाह द्वारा 1500 ई. में इस तालाब का निर्माण करवाया गया, इसलिए उन्हीं के नाम पर दल सागर नाम रखा गया। यहां तालाब के बीच में टापू बना है। तालाब राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लगभग 50 एकड़ भू-क्षेत्र में फैला है।

वैनगंगा नदी

वैनगंगा नदी सिवनी जिले की जीवनधारा के रूप में जानी जाती है। इस नदी का उद्गम स्थल गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर पूर्वी दिशा में ग्राम मुंडारा में हुआ है। यहां एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित भीमगढ़ संजय सरोवर बांध है। यह बांध वैनगंगा नदी पर जिले के छपारा ब्लॉक के अंतर्गत भीमगढ़ में बना हुआ है। यह नदी सिवनी की अर्द्ध परिक्रमा करती हुई लखनवाड़ा दिघोरी बंडोल छपारा होते हुए बालाघाट जिला, भंडारा तथा चांदा जिले से बहती हुई वर्धा नदी में मिल जाती है।

पेंच राष्ट्रीय उद्यान

जिले का मुख्य आकर्षण पेंच टाइगर सेंचुरी है जो जबलपुर से 192 और नागपुर

से 92 किलोमीटर की दूरी पर है। सिवनी जिले में पर्यटन के रूप में पेंच राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण के लिए जाने के दो गेट हैं। पहला गेट सिवनी से नागपुर रोड पर 20 किलोमीटर ग्राम सुकतरा से पश्चिम दिशा में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम कर्माझिरी से तथा दूसरा सिवनी से नागपुर रोड पर सिवनी से 50 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम खवासा से 12 किलोमीटर पश्चिम में टुरिया ग्राम से है। दोनों गेटों पर वन विभाग, पर्यटन विभाग एवं प्रायवेट होटल एवं वाहनों की सुविधा पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहती है। पार्क माह अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोला जाता है तथा जून-जुलाई के बाद बंद कर दिया जाता है।

मोंगली लैंड, छुई (कांहीवाड़ा)

नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग जब भारत लौटे और लगभग साढ़े छह साल तक यहीं रह कर कार्य किया। उनके द्वारा लिखी गयी कहानी द जंगल बुक के कथानक में मोगली नामक एक बालक है जो जंगल में खो जाता है और उसका पालन पोषण भेड़ियों का एक झुंड करता है, अंत में वह गांव में लौट जाता है। इसलिए इस जिले को मोंगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है।

मछली बीज - जिले के जेवनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित है।

सीताफल- जिले के छपारा तहसील में उत्पादित होने वाला सीताफल विशेष गुणवत्ता एवं स्वाद के लिए जाना जाता है।

मक्का - जिले की प्रमुख खरीफ फसल मक्का है।

कृषि के क्षेत्र में नवाचार

आत्मा तथा बायफ कन्वर्जेंस के मार्गदर्शन में विगत वर्षों में किए गए लगातार प्रयासों के फलस्वरूप घंसौर विकासखंड (सिवनी के जनजातीय दूरस्थ ब्लॉक) के ग्राम दुजनपुर, बरेला, गोरखपुर, अतरिया, विनेकी कला, पनारझिर, जमोड़ी, डोभी खुदार गांव बगदरी में आम, आंवला और काजू आदि का वृक्षारोपण किया गया है। इन प्रयोगों से होकर कृषकों का फल उत्पादन की ओर रुझान बढ़ रहा है। यहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत धान का श्री पद्धति से रोपा लगाया जा रहा है। कृषक कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषकों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित किया जाता है।

मकर संक्रांति पर्व मेला

सिवनी में मकर संक्रांति के अवसर पर पावन वैनगंगा तटों में जगह-जगह मेला लगता है। वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल मुंडारा के अलावा मुंगवानी, दिघौरी, मझगवां, कोठीघाट, सिद्धघाट, पंचधारा, उगली, भीमगढ़ डैम और हिर्री वैनगंगा संगम संरेखाकला में श्रद्धालु स्नान करते हैं और मेला लगता है।

सिद्धघाट तहसील मुख्यालय केवलारी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर वैनगंगा नदी पर स्थित है। सिद्धघाट में वैनगंगा नदी के मध्य में सिद्धबाबा (शिव

जी) का मंदिर है, जो बड़ी-बड़ी चट्टानों के ऊपर स्थित है। अपनी विशेष स्थलाकृति के कारण सिद्धघाट सिवनी का भेड़ाघाट भी कहलाता है।

श्री शिवधाम मठ-घोघरा लखनादौन

जिला मुख्यालय से जबलपुर रोड पर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर विकासखंड लखनादौन है। लखनादौन मुख्यालय से पश्चिम दिशा में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम मठघोघरा है। यह प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। इसमें दो पहाड़ी के बीच में एक गहरी गुफा है जिसमें भगवान शिव की मूर्ति और शिवलिंग है।

रिछारिया बाबाजी मंदिर धनौरा

सिवनी जिले के विकासखंड धनौरा में रिछारिया बाबा का बहुत ही प्रसिद्ध, ऐतिहासिक मंदिर है। यहां पर दीपावली के बाद 15 दिन का मेला लगता है। मेले में बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं। ग्रामीणजन मेले में खरीददारी करते हैं तथा रिछारिया बाबा की पूजा-अर्चना भी करते हैं। मुख्य मंदिर में काले पत्थर की भगवान विष्णु की अष्टभुजी मूर्ति स्थापित है और मंदिर के आस-पास अन्य मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर की मूर्तियां तथा अन्य अवशेष लगभग 10वीं शताब्दी की हैं।

- देवेन्द्र गोरे
(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

खेल चर्चा

यूएस ओपन की मिश्रित युगल स्पर्धा के नियमों में बदलाव

न्यूयॉर्क, अमेरिकी टेनिस संघ ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के नियमों में बदलाव किए है। संघ यूएस ओपन के मिश्रित युगल चैंपियनशिप का आयोजन टूर्नामेंट शुरू होने से एक हफ्ते पहले कराएगा और उसे उम्मीद है कि प्रारूप में बदलाव तथा 10 लाख डॉलर की इनामी राशि से शीर्ष एकल खिलाड़ी ग्रैंडस्लैम युगल खिताब जीतने के लिए चुनौती पेश करेंगे। इस साल की स्पर्धा में 16 टीम दो दिन तक छोटे मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा करेंगी। इससे खेल के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी आकर्षित हो सकते हैं जिनमें से कई खुद को एकल के लिए तरोताजा रखने के लिए लंबे समय से युगल से दूर रहे हैं। घोषित योजना के अनुसार 19 और 20 अगस्त को मिश्रित युगल मुकाबले खेले जाएंगे। अमेरिकी टेनिस संघ के कार्यकारी निदेशक और सीईओ ल्यू शेर ने कहा कि इसके पीछे का कारण अधिक प्रशंसकों को आकर्षित करना और दुनिया भर में प्रशंसकों का आधार बढ़ाना है।

38वें नेशनल गेम्स

मध्यप्रदेश 82 पदकों के साथ राज्यों की सूची में तृतीय स्थान पर

देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश ने 34 स्वर्ण, 26 रजत और 22 कांस्य सहित कुल 82 पदक जीते हैं। मध्यप्रदेश पदक तालिका में चौथे तथा राज्यों की सूची में तीसरे स्थान पर रहा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से उनके अनुभव साझा किए और उनकी मेहनत, समर्पण और सफलता की सराहना की।

श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ की कड़ी मेहनत और समर्पण भाव के कारण ही प्रदेश ने 38वें नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 82 पदकों के साथ राज्यों की सूची में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। श्री सारंग ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का संकल्प लें और स्वर्ण पदक हासिल करने को अपना लक्ष्य बनाएं। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत, आत्मविश्वास और समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर विश्वास रखें, हर चुनौती को अवसर में बदलें और विजय के शिखर तक पहुंचे। श्री सारंग ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए यह भी कहा कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर खिलाड़ियों को सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर है, जिससे वे अपने खेल कौशल को निखारकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें।

पदक तालिका (टॉप-10)

राज्य का नाम	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
सर्विसेज	68	26	27	121
महाराष्ट्र	54	71	76	201
हरियाणा	48	47	58	153
मध्यप्रदेश	34	26	22	82
कर्नाटक	34	18	28	80
तमिलनाडु	27	30	35	92
उत्तराखंड	24	35	44	103
पश्चिम बंगाल	16	13	18	47
पंजाब	15	20	31	66
दिल्ली	15	18	29	62

खेलों के विकास के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध

श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं और प्रशिक्षण देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस दिशा में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिससे भविष्य में और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। प्रदेश के विजयी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए श्री सारंग ने आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश के खिलाड़ी देश और दुनिया में अपनी सफलता की नई गाथा लिखेंगे।

भारत ने हॉकी प्रो लीग में जर्मनी को हराया

भुवनेश्वर, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी प्रो लीग में विश्व चैम्पियन जर्मनी को मात दी है। प्रो लीग में भारत और जर्मनी के बीच खेले गए दूसरे मुकाबले में भारत ने 1-0 से जीत दर्ज की। मैच का एकमात्र गोल भारत के गुरजंत सिंह ने किया। मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। भारतीय टीम ने मैच में आक्रामक रणनीति के साथ शुरुआत की। गुरजंत ने पहले क्वार्टर के चौथे मिनट में बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई, जो अंत तक कायम रही। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के कई मौके बनाए लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी।

दिपाली देशपांडे बनीं निशानेबाजी की मुख्य कोच

नई दिल्ली, राष्ट्रीय राइफल संघ ने देश की पूर्व निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित दिपाली देशपांडे को मुख्य कोच नियुक्त किया है। राष्ट्रीय राइफल संघ ने बताया कि दिपाली देशपांडे को राइफल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, जबकि पूर्व ओलंपियन जसपाल राणा को हाई परफॉर्मेंस कोच (25 मीटर राइफल शूटिंग) नियुक्त किया गया है। संघ की गवर्निंग बॉडी की बैठक में राष्ट्रीय निशानेबाजी टीमों के लिए कोच नियुक्त किए गए हैं। संघ ने 19 कोचों को बरकरार रखा है, जबकि 16 नए सदस्य कोचिंग टीम में शामिल किए गए हैं।

आईपीएल का शेड्यूल जारी

कोलकाता में खेला जाएगा आईपीएल का फाइनल मुकाबला

मुंबई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन (आईपीएल-2025) का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आईपीएल-2025 का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 22 मार्च को खेला जाएगा। 25 मई को इसी मैदान पर टूर्नामेंट का फाइनल भी खेला जाएगा।

आईपीएल-2025 में 10 टीमों के बीच कुल 74 मैच खेले जाएंगे, इनमें नॉकआउट यानी प्लेऑफ के मुकाबले भी शामिल हैं। टूर्नामेंट के लीग मुकाबले 22 मार्च से 18 मई के बीच खेले जाएंगे।

तेरह शहरों में खेले जाएंगे मैच

आईपीएल के 18वें सीजन के मैच कुल 13 शहरों में खेले जाएंगे। आईपीएल-2025 के मैच लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, बेंगलुरु, न्यू चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता और धर्मशाला में खेले जाएंगे। आईपीएल 2025 में कुल 12 डबल हेडर मैच हैं। यानी इसका मतलब है कि एक दिन में दो-दो मैच खेले जाएंगे।

हर वर्ष आईपीएल का पहला मैच पिछले सीजन फाइनल खेलने वाली दोनों टीमों के बीच होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले सीजन यानी आईपीएल-2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भिड़ंत हुई थी, लेकिन आईपीएल-2025 का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा।

- आईपीएल-2025 में कुल 10 टीमें लेंगी हिस्सा।
- टूर्नामेंट में फाइनल सहित कुल 74 मैच खेले जाएंगे।

तेजस ढींगरा ने जीती राष्ट्रीय घुड़सवारी चैम्पियनशिप

मेरठ, युवा घुड़सवार तेजस ढींगरा ने एक बार फिर घुड़सवारी प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम करते हुए खिताब जीत लिया है। तेजस ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय घुड़सवारी चैम्पियनशिप (शो जंपिंग) जीती है। चैम्पियनशिप में बीयास राइडिंग फैसिलिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए तेजस ने चैम्पियनशिप टूर में 16 अंक हासिल करते हुए खिताब जीता।

गुलवीर ने तीन हजार मीटर इंडोर रेस में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

बोस्टन, भारत के अनुभवी धावक गुलवीर सिंह ने तीन हजार मीटर इंडोर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर ने अमेरिका के बोस्टन में आयोजित एक प्रतियोगिता में तीन हजार मीटर दौड़ का 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुलवीर ने स्पर्धा में सात मिनट 38.26 सेकेंड का समय निकालकर रेस पूरी की। इससे पहले इस स्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड गुलवीर सिंह के कोच सुरेंदर सिंह के नाम था, सुरेंदर ने वर्ष 2008 में यह रेस सात मिनट 49.47 सेकेंड में पूरी की थी।

पंकज आडवाणी ने जीता 36वां राष्ट्रीय खिताब

इंदौर, भारत के अनुभवी और स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने नाम एक और खास उपलब्धि दर्ज कर ली हैं। पंकज ने इंदौर के यशवंत क्लब में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब हासिल किया।

पंकज ने टूर्नामेंट के फाइनल में ब्रजेश दमानी को हराया। फाइनल मैच में ब्रजेश दमानी शुरुआत में कामयाब रहे, लेकिन बाद में पंकज उनसे आगे निकल गए। पंकज ने अंतिम फ्रेम में 84 का प्रभावशाली ब्रेक दिया और इस फ्रेम के साथ ही मैच और चैंपियनशिप दोनों अपने नाम कर ली। इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर ही एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। पंकज ने अपने प्रदर्शन में निरंतरता और सटीकता बनाए रखी। एक फ्रेम से पिछड़ने के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और फिर कोई गलती नहीं की।

ब्रजेश ने ग्रुप चरण में पंकज को हराया था, लेकिन फाइनल में वह इस अनुभवी

खिलाड़ी के खिलाफ अपनी लय बरकरार नहीं रख पाए। ब्रजेश के खिलाफ ग्रुप चरण के मैच में आडवाणी केवल एक फ्रेम जीतने में सफल रहे थे। पंकज और ब्रजेश अब एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

पंकज ने चैंपियनशिप जीतने के बाद कहा कि यह एकमात्र प्रतियोगिता थी जिसके प्रदर्शन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। इसलिए इस प्रतियोगिता में काफी कुछ दांव पर लगा था। यहां स्वर्ण पदक जीत कर बहुत अच्छा लग रहा है।

अमांडा अनिसिमोवा ने जीता कतर ओपन

दोहा, अमेरिका की युवा टेनिस खिलाड़ी अमांडा अनिसिमोवा ने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग के फाइनल में अमांडा ने लात्विया की जेलेना ओस्तापेंको को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराया। फाइनल मुकाबला बारिश के कारण प्रभावित रहा। मैच के पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहले सेट में ओस्तापेंको की कड़ी चुनौती के बावजूद अमांडा जीत दर्ज करने में सफल रहीं। दूसरे सेट में अमांडा ने पूरी तरह अपना दबदबा बनाया और पूर्व फ्रेंच ओपन चैम्पियन ओस्तापेंको को 6-3 से हरा दिया।

मनु भाकर बनीं बीबीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी

लंदन, भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बीबीसी वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी चुना गया। मनु इस पुरस्कार के लिए नामित पांच लोगों में शामिल थीं। इनमें गोल्फर अदिति अशोक, पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना और पहलवान विनेश फोगाट शामिल हैं। खेल पत्रकारों और लेखकों की एक प्रतिष्ठित जूरी ने नामांकित खिलाड़ियों का चयन किया था।

भारत में महिला खिलाड़ियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार का यह पांचवां सत्र है। बाइस वर्षीय मनु को पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने के लिए यह पुरस्कार मिला। वह एक ओलंपिक इवेंट में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा के साथ-साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था।

- मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में जीते थे दो कांस्य पदका
- मनु एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं।
- मनु को इस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

पुरस्कार समारोह में अन्य पुरस्कार विजेताओं में पैरा तीरंदाज शीतल देवी (बीबीसी वर्ष की उभरती हुई खिलाड़ी), भारत की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज (बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार) और पैरा निशानेबाज अवनी (बीबीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा खिलाड़ी) शामिल रहीं। वहीं महिला शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव को बीबीसी चेंजमेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मनु ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और ओलंपिक सफलता की अपनी यात्रा का जिक्र किया। मनु ने कहा कि मुझे सम्मानित करने के लिए मैं बीबीसी को धन्यवाद देती हूं। कुछ वर्ष पहले मैंने बीबीसी वर्ष की उभरती हुई खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था और अब इस वर्ष मुझे बड़ा पुरस्कार मिला है। मेरी यात्रा उतार-चढ़ाव से भरी रही। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के बाद मैंने बहुत संघर्ष किया, कई स्पर्धाएं हारी लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हुई, यह जारी रही। आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं और मैंने पेरिस में ऐसा किया है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

इसरो फिर करेगा स्पेडेक्स मिशन में अन-डॉकिंग और डॉकिंग

अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को जोड़ने की जटिल डॉकिंग तकनीक के सफल प्रदर्शन के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एक बार फिर मिशन स्पेडेक्स में अन-डॉकिंग और डॉकिंग प्रयोग की तैयारी में है। पहले दोनों उपग्रहों को एक-दूसरे से अलग (अन-डॉकिंग) किया जाएगा और फिर उन्हें जोड़ा (डॉकिंग) जाएगा। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा कि स्पेडेक्स मिशन के दोनों उपग्रहों को आपस में जोड़ने के बाद प्रक्रियाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। स्पेडेक्स मिशन केवल दोनों उपग्रहों को जोड़ने तक ही सीमित नहीं है। उपग्रहों की अन-डॉकिंग और फिर से डॉकिंग होगी। उसके बाद यह कई बार और दोहराएंगे।

अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार रूस

अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए रूस सहमत हो गया है। रूस ने कहा कि रूस और अमेरिका का ध्यान अब युद्ध पर नहीं बल्कि शांति पर है। दोनों देश शांति के मुद्दे पर बात करेंगे। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच फोन पर बातचीत शक्तिशाली संकेत है कि चर्चा से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। मौजूदा हालातों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात महत्वपूर्ण है। रूस पर लगे प्रतिबंधों पर टिप्पणी करते हुए प्रेसकोव ने कहा कि इनको जल्दी हटाया भी जा सकता है।

एलन मस्क ने लॉन्च किया एआई चैटबॉट ग्रोक-3

एलन मस्क की कंपनी एक्सएआई ने नया और स्मार्ट इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक-3 लॉन्च किया है। मस्क ने ग्रोक-3 को दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बताया। उन्होंने कहा हम ग्रोक-3 को लॉन्च करने के लिए उत्साहित हैं। इस एआई में उन्नत तर्कशक्ति, टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्जन और सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म शामिल है। मस्क ने दावा किया कि ग्रोक-3 ने विज्ञान, कोडिंग और गणित में एआई की दुनिया के प्रमुख नामों जैसे गूगल के जेमिनी-2 प्रो, डीपसीक वी-3 और ओपन एआई के जीपीटी-4 ओ को पीछे छोड़ दिया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किये महत्वपूर्ण विषयों पर समझौते

रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने भारत के साथ रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन का विस्तार करेगा अमेरिका

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही देश के प्रमुखों ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की क्षमता की पुष्टि की। यह साझेदारी आपसी विश्वास, साझा हितों, सद्भावना और अपने नागरिकों की मजबूत भागीदारी पर आधारित है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21वीं सदी के लिए यूएस-इंडिया कॉम्पैक्ट (सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करना) का शुभारंभ किया। इस पहल के अंतर्गत, उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के लिए विश्वास के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए इस वर्ष प्रारंभिक परिणामों के साथ परिणाम-संचालित एजेंडे के लिए प्रतिबद्धता जताई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान

रक्षा के लिए दो वर्षीय फ्रेमवर्क

अमेरिका-भारत रणनीतिक हितों पर दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में फैली एक गतिशील रक्षा साझेदारी के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने इस वर्ष 21वीं सदी में यूएस-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए दस वर्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा की। अमेरिका अंतर-संचालन और रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन का विस्तार करेगा।

ऊर्जा सुरक्षा

दोनों देश आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और तकनीकी नवाचार के लिए मौलिक है। उन्होंने ऊर्जा की वहनीयता, विश्वसनीयता और उपलब्धता तथा स्थिर ऊर्जा बाजार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका-भारत सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को आगे बढ़ाने में अग्रणी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में अमेरिका और भारत की भूमिका को समझते हुए, नेताओं ने तेल, गैस और अक्षैय परमाणु ऊर्जा सहित अमेरिका-भारत ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किफायती ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने और अपने नागरिकों के लिए किफायती ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया।

प्रौद्योगिकी और नवाचार

यूएस-इंडिया ट्रस्ट (रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संबंधों में परिवर्तन) पहल की शुरुआत की घोषणा की, जो रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार-से-सरकार, शिक्षा और निजी क्षेत्र के सहयोग को उत्प्रेरित करेगी, जबकि सत्यापित प्रौद्योगिकी विक्रेताओं के उपयोग को प्रोत्साहित कर सुनिश्चित करेगी कि संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा की जाए।

बहुपक्षीय सहयोग

अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए है। क्वाड भागीदारों के रूप में, नेताओं ने दोहराया कि साझेदारी आसियान केंद्रीयता की मान्यता; अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुशासन का पालन; सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता, ओवरफ्लाइट और अन्य समुद्रीय वैध उपयोगों के लिए समर्थन और वैध वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुसार समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत द्वारा समर्थित है।

व्यापार और निवेश

दोनों नेताओं ने अपने नागरिकों को समृद्ध, राष्ट्रों को मजबूत, अर्थव्यवस्थाओं को अधिक नवीन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सरल बनाने के लिए व्यापार और निवेश के विस्तार का संकल्प लिया। उन्होंने निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोज़गार सृजन करने वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों का संकल्प लिया। इसके लिए, द्विपक्षीय व्यापार के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया- "मिशन 500"- जिसमें वर्ष 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक कर 500 बिलियन डॉलर करना है।

28 अरब डॉलर तक पहुंचेगा भारत और कतर का कारोबार

भारत और कतर ने अपने संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताते हुए कहा कि दोनों देश अगले पांच साल में द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना कर 28 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत और कतर के बीच इसी सिलसिले में एक समझौते का भी आदान-प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई।

बिन जसीम अल थानी सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया और व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की।

पंद्रह अरब डॉलर का है दोनों देशों के बीच व्यापार

भारत में कतर का निवेश 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। इसमें कतर का भारत में टेलीकॉम, रिटेल और बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल है। कतर के हालिया निवेशों में रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 1 अरब डॉलर और 2023 में इंडोस्पेस लॉजिस्टिक्स पार्क्स में 393 मिलियन डॉलर शामिल हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 15 अरब डॉलर का है। चर्चा में भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान

ऊर्जा पर भी दोनों देशों के बीच हुई बात

कतर भारत के तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग को और बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कतर की सरकारी स्वामित्व वाली कतर एनर्जी ने भारत के पेट्रोनेट एलएनजी के साथ अपने दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्ति समझौते को बढ़ाया।

आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन शुरू करने की घोषणा की

आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 2025 के संस्करण (आईडीवाई 2025) के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा की है। ये पुरस्कार योग के प्रचार और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण और निरंतर योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देते हैं। समाज पर योग के गहन प्रभाव को सम्मानित करने के लिए स्थापित प्रधानमंत्री योग पुरस्कारों का उद्देश्य क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान का जश्न मनाना, रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और जीवनशैली संबंधित विकारों के प्रबंधन में योग की भूमिका को सुदृढ़ करना है। प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से समर्थित ये पुरस्कार योग के विकास और प्रचार में अमूल्य योगदान को मान्यता देने और उसका जश्न मनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय व्यक्ति, राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे।

मिशन समुद्रयान

चौथी पीढ़ी की भारतीय स्वदेशी वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य-6000 का परीक्षण संपन्न

भारत को जल्द ही वैज्ञानिक पनडुब्बी मिलने वाली है। चौथी पीढ़ी की स्वदेशी वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य-6000 ने बंदरगाह पर भार (वेट) परीक्षण पूरा कर लिया है। गहरे समुद्र के रहस्यों का पता लगाने वाली भारत की महत्वाकांक्षी समुद्रयान परियोजना के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है।

गहराई में उतरने का मार्ग प्रशस्त हुआ

इस सफलता से मत्स्य-6000 के इसी वर्ष समुद्र में 500 मीटर तक की गहराई में उतरने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। डिजाइन पूरा होने के बाद पनडुब्बी के एकीकरण और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कई परीक्षण किए गए थे। इन परीक्षणों के बाद इसे वेट टेस्ट और कार्यक्षमता प्रदर्शन करने के लिए 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक चेन्नई के पास कट्टुपल्ली बंदरगाह पर स्थित एलएंडटी शिपबिल्डिंग केंद्र में ले जाया गया था। परीक्षणों का उद्देश्य कई महत्वपूर्ण मापदंडों पर पनडुब्बी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था।

अब समुद्र में 500 मीटर की गहराई में होगा टेस्ट

नेविगेशन और संचार क्षमताओं की जांच की गई। वैज्ञानिक पेलोड, जिसमें कई समुद्र विज्ञान सेंसर शामिल थे, उनकी कार्यक्षमता की पुष्टि करने के लिए परीक्षण किए गए। बंदरगाह में पानी की गहराई सीमित होने के कारण, पानी के भीतर ध्वनि संचार कम प्रभावी था। अब समुद्र में 500 मीटर की गहराई तक उथले पानी में इसका परीक्षण किया जाएगा।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को मत्स्य-6000 को डिजाइन और विकसित करने का कार्य सौंपा है। इसका उद्देश्य समुद्री अन्वेषण के लिए तीन लोगों को समुद्र में छह हजार मीटर की गहराई तक ले जाना है। मत्स्य-6000 की प्रमुख विशेषताओं में सभी दिशाओं में गति के लिए थ्रस्टर्स, बिजली आपूर्ति के लिए बैटरी बैंक शामिल हैं। इसमें उन्नत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आधुनिक अंडरवाटर नेविगेशन उपकरण भी हैं।

मिशन से होगा फायदा

समुद्रयान मिशन के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य-6000 केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को अनुमानित 1000 से 5500 मीटर की गहराई पर गैस हाइड्रेट्स, पॉलिमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल्स, हाइड्रो-थर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट्स जैसे संसाधनों की गहरे समुद्र में खोज करने में सुविधा प्रदान करेगा।

मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर बनाया न्यू गाजा प्लान

मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना से हमास को अलग रखा गया है। मिस्र की यह योजना अमेरिका की गाजा को 'मध्य पूर्व के रिवेरा' योजना बनाने का विकल्प है। मिस्र ने कहा कि उसकी योजना के अनुसार हमास को गाजा की सत्ता और पुनर्निर्माण से योजना से अलग रखा जाएगा।

मिस्र ने कहा कि गाजा में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को सामाजिक और सामुदायिक सहायता समिति के नियंत्रण में सौंपा जाएगा।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक- डॉ. सुदाम खाड़े, मुद्रक- डॉ. सुदाम खाड़े द्वारा मेसर्स डी.वी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- रंजना चितले।